सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 71, नई दिल्ली । गुरुवार, 23 मई 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

कुछ लोग केवल सफल होने के सपने देखते हैं जबकि अन्य लोग जाते हैं और इसके लिए कठिन मेहनत करते हैं।

03 1 जून से नाबालिग के गाडी चलाने पर, 25000 जुर्माना, रजिस्ट्रेशन रद्द के साथ पेरेंट्स पर कारवाई

06 मतदान में युवाओं की अत्यावश्यक भूमिका

08 गर्मी-बारिश ने क्यों बढ़ा दी किसानों और सरकार की टेंशन?

ओवरटेक करने से पहले अपने आप को निम्न सवालो का जवाब अवश्य दें : अंकुर शरण, टोलवा, एवं ओमनी फाउंडेशन

संजय बाटला

1. क्या यह सुरक्षित है ?
2. क्या यह कानून और नियम के अनुसार है ?
3. क्या यह लेना जरूरी है ?

हमारी तरफ से आप को नर्म निवेदन प्रार्थना:- कृप्या करके निम्नलिखित पर ओवरटेक न करें

1. पुल पर:- पुलों पर ओवरटेक करने से बचें, ओवरटेक करने के लिए पुल खतरनाक स्थान हैं क्योंकि आपके पास पानी के अंदर जाने के अलावा कोई अन्य जगह नहीं है या जब आप ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं तो अचानक दूसरी कारें सामने आ जाती हैं तो विरोधी कारों से टकरा जाते हैं।

2. मोड़ पर:- जब कोई मोड़ हो, तो कृपया ओवरटेक न करें, भले ही आपको लगे कि सड़क कितनी भी साफ है, यह बहुत खतरनाक है क्योंकि आप सामने नहीं देख सकते हैं, और हो सकता है कि दूसरी तरफ से कोई तेज गति में वाहन आ रहा हो।

3. पहाड़ी की चोटी पर:- जैसे किसी मोड़ पर, पहाड़ और पहाड़ियां ओवरटेक करने के लिए गलत स्थान हैं, आप सामने से आने वाले को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं और आप ओवरटेक करने के प्रयास में विपरीत दिशा से आने वाले यातायात से टकराने से बचने में सफल नहीं हो पाएंगे।

4. नुकीले कोने:- ओवरटेक करना खतरनाक है क्योंकि आपका ब्रेक सिस्टम आपके अनुमान के अनुसार काम नहीं कर सकता है।

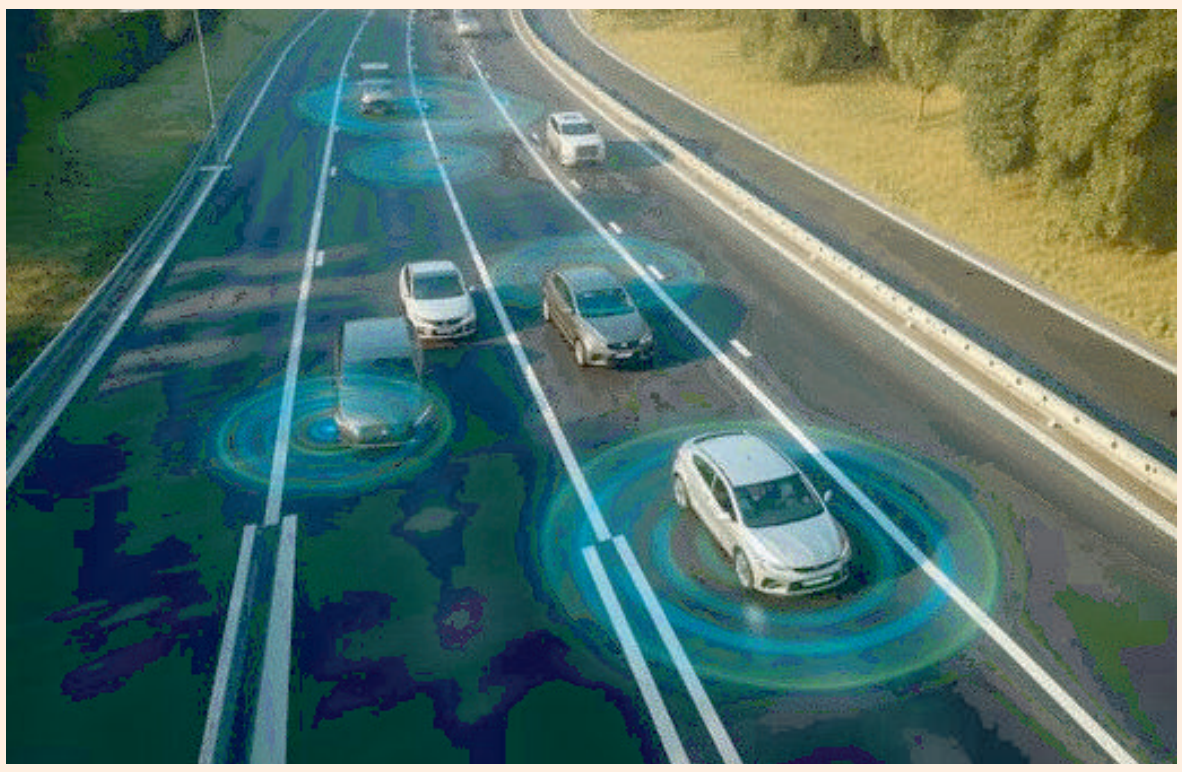

5. जब आपके सामने वाला वाहन सिग्नल देता है तो वह दाहिनी ओर मुड़ना चाहता है अतः आप अपने वाहन की गति धीमी करें और सड़क अनुमति दे तो उस वाहन को मुड़ने दें या सुरक्षित रूप से बाईं ओर निकल जाएं।

6. जब आप किसी भी कारण से सामने का भाग स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं तो कृप्या ओवरटेक न करें।

7. जब बारिश हो रही हो:- जब भारी बारिश हो तो ओवरटेक न करें क्योंकि सड़क फिसलन भरी हो सकती है और आपकी दृश्यता ख़राब हो सकती है।

8. जब आप तेज गति से चलने वाली कारों के काफिले का पीछा कर रहे हों:- काफिले में तेज गति से चलने वाली कारों को ओवरटेक करने से बचें, ऐसा करना खतरनाक होगा।

9. जब सड़क बहुत संकरी हो:- कुछ सड़कें इतनी संकरी होती हैं कि एक ही समय में दो वाहन नहीं चल सकते, इस प्रकार की सड़कों पर ओवरटेक करने से बचें।

10. जब सड़क फिसलन भरी हो:- बारिश, पानी, फिसलन भरा तेल और दलदली क्षेत्र फिसलन वाले माने जाते हैं, ऐसे क्षेत्रों में ओवरटेक करने से सावधान रहें।

11. आक्रामक ड्राइवर:- आक्रामक ड्राइवरों से आगे निकलने से बचें, यह वह ड्राइवर हैं जो जब भी आप उनसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं तो वह आपको ओवरटेक करने से रोकने के लिए अपनी गति बढ़ा देते हैं। इस प्रकार के ड्राइवर सड़क को रेस ट्रैक के रूप में देखते हैं, वह खतरनाक ड्राइवर होते हैं और आसानी से सड़क दुर्घटना का कारण बन सकते हैं।

12. रात में गाड़ी चलाना:- रात में गाड़ी चलाने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, यदि आप स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं तो कृप्या ओवरटेक न करें, यदि आपकी दृष्टि अच्छी नहीं है तो रात में गाड़ी न चलाएं। इस तरह से गाड़ी चलाएं कि आपको सफर में किसी भी प्रकार की दुर्घटना का सामना ना करना पड़े क्योंकि आपके इन्तजार में घर पर परिवार है

ओवरटेकिंग हमारी सड़कों पर दुर्घटनाओं और जाम का सबसे बड़ा कारण है: राकेश जैन, ओमनी फाउंडेशन

भारत देश में सरकारों और प्रशासन के साथ विभागो खास तौर से परिवहन विभाग की कमियों के कारण लोग लेन ड्राइव के बारे मे जानते ही नहीं है और ना ही उनके बस में इन्तजार करना रहा है जिस कारण उन्हें जहां भी जगह उपलब्ध हो बाएं या दाएं से आगे निकल जाते हैं। मोड़ों, पुलों, फिसलन भरी सड़कों, एक तरफ़ा सड़कों, ठोस रेखाओं को पार कर और ना जाने क्या-क्या कर के लोग आगे निकल जाते हैं, भले ही ऐसा करना खतरनाक हो। कुछ लोग नशे में आगे निकल जाते हैं। लोग बिना दाए बाए देखे जहा से भी मौका मिलता है ओवरटेक करते नजर आते हैं और इसी कारण से वहां खड़ी किसी भी वस्तु / वाहन से टकरा जाते हैं।

**लोग ओवरटेक करने के लिए लेन बदलने का संकेत नहीं देते।

**लोग आगे निकलने के लिए टेढ़ी-मेढ़ी गाड़ी चलाते हैं।

**लोग अपनी उचित लेन में खड़े वाहन से आगे निकलने के लिए गलत लेन में खड़े हो जाते हैं।

अधिकांश लोगों ने लेन और लाइन में गाड़ी चलाना सीखा ही नहीं है। उनमें आगे निकलने का लालच अंतर्निहित होता है जो उनके सामने आता है।

दिल्ली के चुनाव में लगेंगी 1500 बसें, 25 मई को 35 रूट्स पर सवेरे 4 बजे से मिलेगी सेवा

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (डीटीसी) की 1500 बसें 25 मई को चुनाव ड्यूटी में लगाई जाएंगी। बाकी बसें सड़कों पर लोगों को सेवा देंगी। 35 रूट निर्धारित किए गए हैं, जिन पर सुबह चार बजे से बसों का संचालन किया जाएगा। डीटीसी के अधिकारियों ने बताया कि कुल डेढ़ हजार बसों को चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है।

यह बसें चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को लाने ले जाने व अन्य कामों में लगाई जाएंगी। सभी सीएनजी बसें हैं। ई-बसों को चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया गया है। अतिरिक्त बसों को सड़कों पर चलाया जाएगा। मतदान के दिन अवकाश रहेगा। ऐसे में बसों की संख्या कम होने से लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा।

इन 35 रूटों पर सुबह 4 बजे से चलेंगी बसें

दिल्ली में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 35 रूट तैयार किए गए हैं। जिन पर मतदान के दिन सुबह चार बजे से बसें चलेंगी। आम दिनों में सुबह साढ़े छह बजे से बसों का संचालन होता है। इन रूटों में टीकरी बॉर्डर-पंजाबी बाग, आजादपुर-औचंदी बॉर्डर, आजादपुर-कुतुबगढ़, लामपुर बॉर्डर-आजादपुर, दहिसरा बॉर्डर-मोरी गेट, लोनी गोल चक्कर-शिवाजी स्टेडियम, हर्ष विहार-केंद्रीय टर्मिनल, आनंद विहार आईएसबीटी-अवंतिका, रोहिणी, आनंद विहार-उत्तम नगर, मयूर विहार फेज-3-धौला कुआं, नोएडा सेक्टर-34-

आईएसबीटी कश्मीरी गेट, बदरपुर बॉर्डर-मोरी गेट, बदरपुर बॉर्डर-शाहबाद मोहम्मदपुर, आया नगर-बदरपुर बॉर्डर, कापसहेड़ा बॉर्डर-मोरी गेट, नानकहेड़ी बॉर्डर-तिलक नगर, शिकारपुर, दौराला व ढांसा बॉर्डर-तिलक नगर, महरौली-नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, उत्तम नगर-मोरी गेट, बदरपुर-आनंद विहार आईएसबीटी, छतरपुर मेट्रो स्टेशन-नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, नजफगढ़-नेहरू प्लेस, जहांगीरपुरी-निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, अवंतिका-जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। इन रूटों पर सुबह चार बजे से बसे चलने से लोग मतदान करने के लिए जल्द बूथ पर पहुंच सकेंगे।

मतदान केंद्रों पर 24 मई को रवाना होगी पोलिंग पार्टी

हर मतदान केंद्र पर छह सदस्यीय पोलिंग पार्टियां 24 मई को ही तैनात कर दी जाएंगी। इन्हें रहने के लिए मतदान केंद्र पर व्यवस्था की जाएगी। इसमें एक पीठासीन अधिकारी, तीन मतदान अधिकारी, एक सहायक और एक पुलिसकर्मी होगा। इस बार पोलिंग पार्टी में करीब 40 प्रतिशत महिलाएं हैं।

हर संसदीय क्षेत्र में दस-दस पिंक व मॉडल मतदान केंद्र

हर संसदीय क्षेत्र में 10-10 पिंक और माडल मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पिंक मतदान केंद्र विशेषकर महिलाओं के लिए हैं। यहां तैनात मतदान कर्मी भी महिलाएं होंगी। वहीं, माडल मतदान केंद्र पर मतदाताओं के स्वागत में रेड कार्पेट बिछेंगे और बैलून से सजाया जाएगा, ताकि मतदाताओं को मतदान के समय विशेष होने का अनुभव प्राप्त हो सके।

राष्ट्र के प्रिय युवाओं,

मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के बारे में लिख रहा हूं जो हम सभी को प्रभावित करता है—सड़क सुरक्षा। जिन सड़कों पर हम प्रतिदिन यात्रा करते हैं उन्हें सुरक्षित रहने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन यह हमारा ड्राइविंग व्यवहार है जो यह निर्धारित करता है कि वे सुरक्षित रहेंगी या नहीं।

अक्सर कहा जाता है कि गाड़ी चलाना एक विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं। यह विशेषाधिकार एक ज़िम्मेदारी के साथ आता है - अपने लिए, अपने प्रियजनों के लिए, और हमारे साथ सड़क साझा करने वाले सभी लोगों के लिए एक ज़िम्मेदारी। हम नियम जानते हैं; हम जानते हैं कि सड़क पर क्या सही है और क्या गलत। फिर भी, सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े एक अलग ही कहानी बताते हैं, टाली जा सकने वाली त्रासदियों और रोके जा सकने वाले नुकसानों की।

सड़क दुर्घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं में से एक घबराहट है। जब हम घबराते हैं, तो हम तर्कसंगत निर्णय लेने की क्षमता खो देते हैं, जिससे खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। शांत और संयमित रहना आवश्यक है, विशेषकर तनावपूर्ण स्थितियों में। गहरी साँसें लें, दिमाग साफ़ रखें और याद रखें कि घबराने से कोई स्थिति नहीं सुधरती।

रोड रेज एक और प्रमुख मुद्दा है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सड़क पर कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। अन्य ड्राइवरों की हरकतें आप पर हमला नहीं हैं बल्कि केवल मानवीय त्रुटि या अधीरता का परिणाम हैं। क्रोध के साथ प्रतिक्रिया करने से स्थिति और बिगड़ती है, जिससे हर कोई अधिक जोखिम में पड़ जाता है। क्रोध को त्यागने और धैर्य रखने से जीवन बचाया जा सकता है।

सड़कों पर ध्यान भटकाना एक मूक हत्यारा है। चाहे वह फ़ोन कॉल हो, संदेश हो, या किसी यात्री के साथ बातचीत हो, ध्यान भटकाने से हमारा ध्यान उस चीज़ से हट सकता है जो वास्तव में मायने रखती है - सुरक्षित रूप से गाड़ी चलाना। सतर्क और केंद्रित रहें. हर बार जब आप गाड़ी चलाएं, ध्यान भटकने से बचने के लिए सचेत निर्णय लें।

याद रखें, सड़क पर हमारे कार्य हमारे चरित्र और जीवन के प्रति सम्मान को दर्शाते हैं। सुरक्षित ड्राइविंग की आदतें अपनाकर हम न केवल अपनी सुरक्षा करते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी सुरक्षित वातावरण बनाते हैं। आइए हम वह पीढ़ी बनें जो अपनी सड़कों को सुरक्षित बनाती है। आइए हम जिम्मेदारी से गाड़ी चलाएं, शांत रहें, ध्यान भटकने से बचें और धैर्य रखें।

हम सभी मिलकर कुछ अलग कर सकते हैं। आइए अपने ड्राइविंग व्यवहार को बेहतरी के लिए बदलने का संकल्प लें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। सड़क सदैव सुरक्षित है; यह हमारा व्यवहार है जो इसे अन्यथा बनाता है।

सुरक्षित रहें और जिम्मेदारी से गाड़ी चलाएं।

शुभकामनाएं,

अंकुर शरण

नाबालिग बच्चों को प्यार दे, अपना वाहन बिल्कुल नहीं :इंस्पेक्टर सतीश कुमार

परिवहन विशेष न्यूज

फरीदाबाद। जिला फ़रीदाबाद उपायुक्त विक्रम सिंह आईएएस के आदेशानुसार व प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण फरीदाबाद के डीटीओ मनीष सहगल एवं डिप्टी कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस फरीदाबाद उषा के निर्देशनुसार एवं एवं सतीश कुमार ट्रैफिक इंस्पेक्टर ग्रेटर फरीदाबाद व सरदार देवेंदर सिंह सदस्य स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल हरियाणा सरकार के मार्ग दर्शन में मोटर व्हीकल एक्ट 2019 एवं योग जागरूकता अभियान आज अटल पार्क, सेक्टर-2 बल्लबगढ़ मे चलाया गया।

आज इस प्रोग्राम का आयोजन हरियाणा योग आयोग हरियाणा सरकार के सदस्य योग आचार्य जयपाल शास्त्री एवं रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन (रजि.) के द्वारा आज सुब्रह 5.50 बजे करवाया गया सतीश कुमार ट्रैफिक इंस्पेक्टर ग्रेटर फरीदाबाद के द्वारा विस्तार से जानकारी दी गयी कि सड़क पर हमेशा ही चलते समय सभी दुपहिया वाहन को चलाते समय दोनों सवारी को हेलमेट पहनना भारत सरकार के द्वारा अनिवार्य है दुपहिया वाहन चालको को अपने अपने हेलमेट की सेफ़्टी बेल्ट लगाने के बारे में बड़ी जानकारी दी अक्सर हम सभी जल्द बाज़ी में हम सभी वाहन चालक हेलमेट की बेल्ट नहीं लगाते है और सड़क पर कोई झटका लगने से हेलमेट दूर सड़क पर गिर जाता है जिसका सुरक्षा का कोई फ़ायदा नहीं इसलिए हमेशा

हेलमेट की बेल्ट ज़रूर लगाए, दुपहिया वाहन चालको को आईएसआई मार्क हेलमेट ही पहनना अनिवार्य है सभी दुपहिया वाहन पर चालक अपने अपने वाहन में साईड के दोनों शीशे लगाना भी अब अनिवार्य है वरना आपका चालान सड़क पर सीसीटीवी कैमरे एवं ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से कट सकता है और अपने अपने वाहन को सड़क पर चलाते समय हमेशा ही अपनी निर्धारित गति सीमा में ही अपना अपना वाहन चलाए सड़क पर सभी वाहन चालक अपनी अपनी गाड़ी चलाते समय सभी चालक अपनी अपनी लेन में ही हमेशा सड़क पर चले मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में जुर्माने अब 10 गुना पुरे देश एवं सभी प्रदेश में बढ़ चुके है आप सभी अपनी अपनी कार में दोनों सवारी एवं पीछे बैठे हुई सवारी को सीट बेल्ट लगाना अब पूरे देश एवं प्रदेश में अनिवार्य है अपनी अपनी गाड़ी में पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है वरना आपका चालान सड़क पर अब ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सड़क पर एवं सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से कट सकता है किरपा आप सभी प्रेशर होर्न सड़क पर बिलकुल न बजाये इसका जुर्माना 10,000 रूपए हो गया है इसलिए हमेशा ट्रैफिक के नियमो की पालना सड़क पर अबश्य करे आप के साथ आपका परिवार भी जुड़ा हुआ है सड़क पर आपकी छोटी सी गलती आपके परिवार को नुकसान जीवन भर दे सकती है बुलेट मोटरसाइकिल में पटाखा साईंलेंसर या कोई भी साईंलेंसर लगाने पर 10 हज़ार रूपए का चालान कट सकता है वाहन चलाते समय मोबाईल भी बिल्कुल ना चलाए अपने अपने वाहन लो चलाते समय आप सभी कान के अंदर अपनी लीड बिलकुल ना लगाए और सबसे महत्बपूर्ण अगर सड़क पर किसी की दुर्घटना होती है और पीक आवर गोल्डन होरस में सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाओ और भारत सरकार द्वारा ईनाम पाओ इसकी जानकारी भी सभी सदस्यों को आज दी गई।

सतीश कुमार ट्रैफिक इंस्पेक्टर ग्रेटर फरीदाबाद ने साइबर क्राइम 1930 के बारे में एवं 112 के बारे में जानकारी दे गयी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के बारे में बताया की आप सभी सारथी ऐप के माध्यम से अपना लर्निंग लाइसेंस एवं पक्का लाइसेंस बनवा सकते है दूसरा 16 साल से 18 साल तक के सभी बच्चे 50 सीसी वाली स्कूटी ही चला सकते है लाइसेंस बनवा कर डिज़ी लाकर में अपने गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट लाइसेंस, RC वाहन का रेजिस्ट्रशन सर्टिफिकेट , इन्शुरन्स, पोलुशन सर्टिफिकेट 4 चीजे हमेशा अपने अपने वाहन में हमेशा ही रखे

इस अवसर पर रोड सेफ्टी ओमनी फाऊडेशन (रजि.) से परवीन शर्मा ,राकेश गुप्ता,बिजेंद्र सैनी,रिंकू मल्होत्रा एवं हरियाणा योग आयोग हरियाणा सरकार के सदस्य योग आचार्य जयपाल शास्त्री व योग टीम की तरफ से मास्टर तेजपाल शर्मा ,कृष्ण कुमार,मुकेश गुप्ता ,वेद राम सैनी,रामपाल चौहान एवं स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल हरियाणा सरकार एवं मेंबर ऑफ पार्लीमेन्ट के सदस्य सरदार देवेंद्र सिंह भी मोके पर मौजूद थे।

नाबालिग बच्चो को प्यार दे अपना वाहन बिल्कुल नहीं

हेलमेट पुलिस को देखकर नहीं बल्कि अपने परिवार को देखकर पहने

पर्यावरण पाठशाला : प्रकृति से ही हम सभी हैं, तो इसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है : प्रियंका श्रीवास्तव

स्वस्थ पर्यावरण वह है जो लंबे समय तक टिकाऊ रहता है। यह हर किसी के लिए जीवन का स्रोत है। यह हर किसी के जीवन को निर्देशित करता है और उचित वृद्धि और विकास को निर्धारित करता है। हमारे जीवन की अच्छी या बुरी गुणवत्ता हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की गुणवत्ता पर निर्भर करती है।

पर्यावरण - जलवायु, स्वच्छता, प्रदूषण तथा वृक्षों का सभी को मिलाकर बनता है, और ये सभी चीजें यानी कि पर्यावरण हमारे दैनिक जीवन से सीधा संबंध रखता है और उसे प्रभावित करता है। मनुष्य और पर्यावरण एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं। पर्यावरण जैसे जलवायु, प्रदूषण या वृक्षों का कम होना मानव शरीर और स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है।

प्रकृति से ही हम सभी हैं, तो इसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य के साथ-साथ यह हमारा दायित्व भी है जिससे हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छी प्रकृति दे सकें, जिसमें वे खुलकर सांस ले सकें, स्वच्छ वायु व स्वच्छ जल का सेवन कर सकें। यह हमारा दायित्व है।

पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के कई हानिकारक प्रभाव होते हैं। इनमें से कुछ हैं प्रदूषण, अधिक जनसंख्या, अपशिष्ट निपटान, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीनहाउस प्रभाव आदि। हमारे पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाला बड़ा कारण हवा में हानिकारक गैसें हैं।

स्वच्छ वातावरण और स्वच्छ पर्यावरण के निर्माण में युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और उनके प्रयासों से ही आने वाली पीढ़ी लाभान्वित होगी। मानवता हर जगह युवाओं की असीम ऊर्जा, विचारों और योगदान पर निर्भर करती है। आइए आज और हर दिन, लोगों और ग्रह के लिए एक न्यायसंगत और टिकाऊ दुनिया को आकार देने में युवाओं का समर्थन करें और उनके साथ खड़े रहें।

पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है, इसकी रक्षा का फर्ज उठाना है।

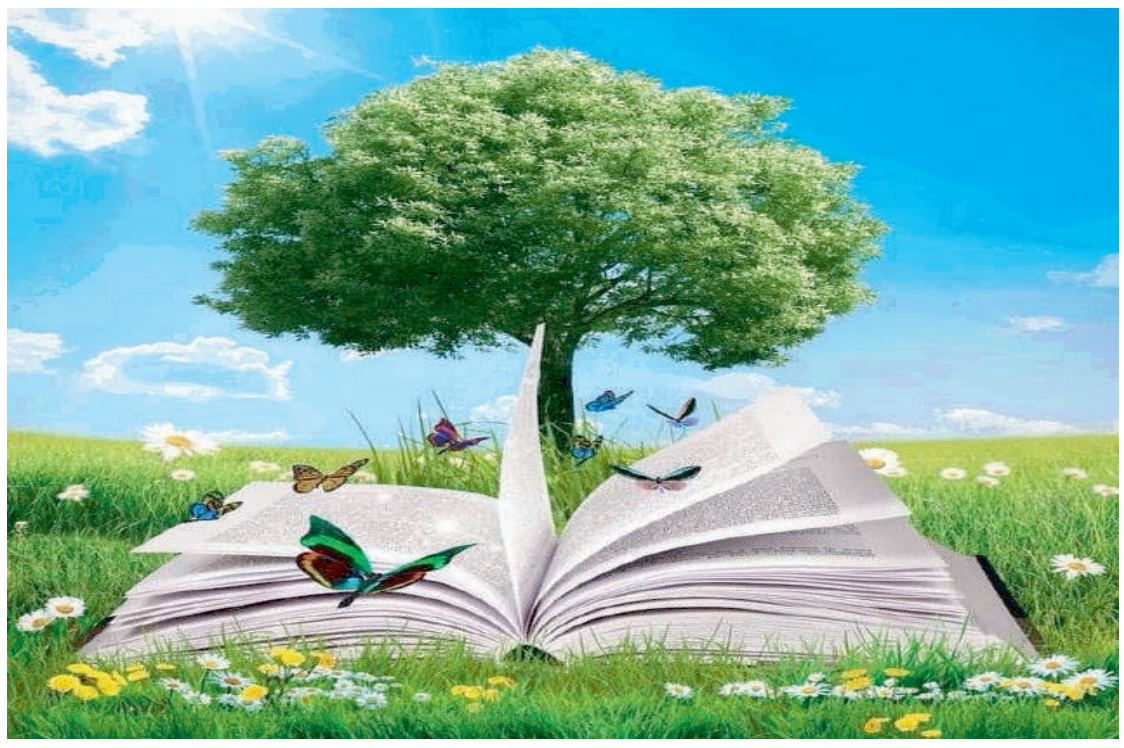

मोहिनी एकादशी व्रत: पाप से दिलाता है मुक्ति

मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। पुराणों के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी है। इस व्रत को करने से निंदित कर्मों के पाप से छुटकारा मिल जाता है तथा मोह बंधन एवं पाप समूह नष्ट होते हैं। सीता की खोज करते समय भगवान श्रीराम ने भी इस व्रत को किया था। उनके बाद मुनि कौंडिन्य के कहने पर धृष्टबुद्धि ने और श्रीकृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया था'

कथा

एक समय भगवान श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, 'हे धर्मराज ! मैं आपसे एक कथा कहता हूं, जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्रीरामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्रीराम बोले कि, 'हे गुरुदेव ! कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुःख का नाश हो जाए। मैंने सीताजी के वियोग में बहुत दुःख भोगे हैं।' महर्षि वशिष्ठ बोले, 'हे राम ! आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है, उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुःखों से छूटकर मोहजाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूं। ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहां धन-धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर व धर्मशाला आदि बनवाए थे। सडक़ों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके पांच पुत्र थे। इनमें से पांचवां पुत्र धृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर-स्त्री के साथ भोग-विलास करता तथा मद्य-मांस का सेवन करता था।

इसी प्रकार के अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने-कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख-प्यास से अति दुःखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुःख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहां वन्य पशु-पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष-बाण लेकर पशु-पक्षियों को मार-मारकर खाने लगा। एक दिन भूख-प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा में स्नान कर आ रहे थे।

मटके का पानी पीने के फायदे

मटके का पीने सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इससे शरीर को ठंडक मिलती है और कई बीमारियों से बचाव भी होता है। गर्मियों में हर किसी को ठंडा पानी पीने का मन करता है। इसके लिए आजकल ज्यादातर घरों में फ्रिज का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्रिज का ठंडा पानी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है? इससे कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में आप गर्मियों में अपनी प्यास बुझाने के लिए फ्रिज का पानी पीने के बजाय मटके का पानी पिएं। आयुर्वेद के अनुसार मिट्टी के घड़े या मटके का पानी अमृत के सामान होता है। मटके में पानी नेचुरल रूप से ठंडा होता है, जो हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। साथ ही, मिट्टी में ऐसे कई तत्व मौजूद होते हैं, जो कई प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता रखते हैं। गर्मियों में मटके का पानी पीने से शरीर की परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो आइए, विस्तार से जानते हैं मटके का पानी के फायदे !

मटके का पानी पीने के फायदे - गर्मियों में मटके में रखा पानी पीने से लू से बचाव होता है। दरअसल, मटके का पानी शरीर में मिनरल्स और ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। यह शरीर को शीतलता प्रदान करता है और गर्मी से संबंधित बीमारियों से भी बचाता है।

1. पाचन तंत्र को दुरुस्त रखे- मटके का पानी पेट के लिए भी फायदेमंद होता है। दरअसल, मिट्टी के बर्तन में रखा पानी नैचुरली एल्कलाइन होता है, जिससे पीएच संतुलन को बनाए रखने में मदद मिलती है। रोजाना मटके का पानी पीने से पेट में गैस, कब्ज और एसिडिटी जैसी पाचन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं।

2. मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है- प्लास्टिक के बर्तनों में बीपीए जैसे हानिकारक केमिकल्स होते हैं, जो सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। प्लास्टिक के कंटेनर में रखा पानी से हार्मोन बाधित होते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म धीमा होता है और वजन बढ़ता है। जबकि, मटके में रखे पानी में कोई हानिकारक केमिकल नहीं होता है। इस पानी को पीने से शरीर का मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा मिलता है।

3. गले के लिए लाभकारी- फ्रिज का पानी पीने से गले में खराश और खांसी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जबकि, मटके का पानी बहुत ज्यादा ठंडा न होने के कारण गले को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है। सर्दी, खांसी और अस्थमा से पीड़ित लोगों को फ्रिज का ठंडा पानी पीने के बजाय मटके का पानी पीना चाहिए। इससे गले से संबंधित किसी तरह की समस्या नहीं होती है।

4. दर्द से राहत पहुंचाए- मटके का पानी पीने से शरीर में दर्द की शिकायत दूर होती है। दरअसल, मिट्टी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो दर्द, ऐठन और सूजन की समस्या को कम करने में मददगार हैं। मटके का पानी पीने से अर्थराइटिस की बीमारी में भी लाभ मिलता है। मटके में रखा पानी पीने से शरीर को कई फायदे मिल सकते हैं। हालांकि, यह जरूर सुनिश्चित करें कि आप नियमित रूप से मटके की सफाई करें।

गुरु अमर दास : सिख पंथ के प्रचारक

गुरु अमर दास जी सिक्ख पंथ के एक महान प्रचारक थे जिन्होंने गुरु नानक जी महाराज के जीवन दर्शन को व उनके द्वारा स्थापित धार्मिक विचाराधारा को आगे बढ़ाया। तृतीय नानक गुरु अमर दास जी का जन्म 5 अप्रैल 1479 को अमृतसर के बसरका गांव में हुआ था। उनके पिता तेज भान भल्ला जी एवं माता बख्त कौर जी एक सनातनी हिन्दू थे। गुरु अमर दास जी का विवाह माता मंसा देवी जी से हुआ था। अमरदास की चार संतानें थी'

समाज सुधार

गुरु अमरदास जी ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया। उन्होंने विधवा विवाह को बढ़ावा दिया और महिलाओं को पर्दा प्रथा त्यागने के लिए कहा। उन्होंने जन्म, मृत्यु एवं विवाह उत्सवों के लिए सामाजिक रूप से प्रासांगिक जीवन दर्शन को समाज के समक्ष रखा। इस प्रकार उन्होंने सामाजिक धरातल पर एक राष्ट्रवादी व आध्यात्मिक आन्दोलन की छाप छोड़ी। उन्होंने सिक्ख धर्म को हिंदू कुरीतियों से मुक्त किया, अंतर्जातीय विवाहों को बढ़ावा दिया और विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति दी। उन्होंने हिंदू सती प्रथा का घोर विरोध किया और अपने अनुयायियों के लिए इस प्रथा को मानना निषिद्ध कर दिया।

लंगर परम्परा की नींव

गुरु अमरदास ने समाज में फैले अंधविश्वास और कर्मकाण्डों में फंसे समाज को सही दिशा दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने लोगों को बेहद ही सरल भाषा में समझाया कि सभी इनसान एक दूसरे के भाई हैं, सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं, फिर ईश्वर अपनी संतानों में भेद कैसे कर सकता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने यह बातें सिर्फ उपदेशात्मक रूप में कही हों, उन्होंने इन उपदेशों को अपने जीवन में अमल में लाकर स्वयं एक आदर्श बनकर सामाजिक सद्भाव की मिसाल कायम की। छूत-अछूत जैसी बुराइयों को दूर करने के लिए लंगर परम्परा चलाई, जहां कथित अछूत लोग, जिनके सामीप्य से लोग बचने की कोशिश करते थे, उन्हीं उच्च जाति वालों के साथ एक पंक्ति में बैठकर भोजन करते थे। गुरु नानक द्वारा शुरू की गई यह लंगर परम्परा आज भी कायम है। लंगर में बिना किसी भेदभाव के संगत सेवा करती है। गुरु जी ने जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए एक परम्परा शुरू की, जहां सभी जाति के लोग मिलकर प्रभु आराधना करते थे।

अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने हर उस व्यक्ति का आतिथ्य स्वीकार किया, जो भी उनका प्रेम पूर्वक स्वागत करता था। तत्कालीन सामाजिक परिवेश में गुरु जी ने अपने क्रांतिकारी कदमों से एक ऐसे भाईचारे की नींव रखी, जिसके लिए धर्म तथा जाति का भेदभाव बेमानी था।

गुरुपद

गुरु अमरदास आरंभ में वैष्णव मत के थे और खेती तथा व्यापार से अपनी आजीविका चलाते थे। एक बार इन्हें गुरु नानक का पद सुनने को मिला। उससे प्रभावित होकर अमरदास सिक्खों के दूसरे गुरु अंगद के पास गए और उनके शिष्य बन गए। गुरु अंगद ने 1552 में अपने अंतिम समय में इन्हें गुरुपद प्रदान किया। उस समय अमरदास की उम्र 73 वर्ष की थी। परंतु अगंद के पुत्र दातू ने इनका अपमान किया।

रचना

अमरदास के कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहीत हैं। इनकी एक प्रसिद्ध रचना 'आनंद' है, जो उत्सवों में गाई जाती है। इन्हीं के आदेश पर चौथे गुरु रामदास ने अमृतसर के निकट संतोषसर नाम का तालाब खुदवाया था, जो अब गुरु अमरदास के नाम पर अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध है।

निधन

गुरु अमरदास का निधन 1 सितम्बर, 1574 को अमृतसर में हुआ था।

महिलाओं में बढ़ती हड्डियों की समस्या

हड्डियां कमजोर होना कई मायनों में खतरनाक है। हड्डियों के कमजोर होने पर छोटा-मोटा झटका या चोट लगने पर इसके टूटने की संभावना बढ़ जाती है। महिलाएं काम में इतना बिजी हो जाती है कि अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रहता, जिसका परिणाम उन्हें बीमारियों के रूप में भुगतना पड़ता है। कैंसर, डायबिटीज के साथ आस्टियोपोरोसिस और हड्डियां टूटना महिलाओं को होने वाली उन्हीं बीमारियों में से है। भारतीय महिलाओं में हड्डियों की कमजोरी की समस्या अधिक देखने को मिलती है, जिसका सबसे बड़ा कारण उनके द्वारा बरती जाने वाली लापरवाही है।

कम उम्र में हड्डियों की कमजोरी

आमतौर पर महिलाओं को लगता है कि ये बीमारियां बड़ी उम्र में ही होती हैं, लेकिन आजकल 20-30 साल में ही महिलाओं में यह समस्या देखने को मिल रही है। दरअसल आजकल महिलाएं घर का भोजन खाने की बजाय जंक फूड्स, फास्ट फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स और हाई फैट फूड्स का सेवन अधिक कर रही हैं, जो उनकी हड्डियों को कमजोर करके आस्टियोपोरोसिस की आशंका बढ़ा देते हैं।

मनोपॉज के बाद बढ़ जाता है खतरा

मनोपॉज की स्थिति में महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर गिर जाता है, जिसके कारण अस्थियां कमजोर होने लगती हैं। वहीं, जिन महिलाओं में अस्थियों का घनत्व तेजी से कम होता है, उन्हें आस्टियोपोरोसिस होने का खतरा अधिक होता है। मनोपॉज से पहले ही अपनी हड्डियों का ख्याल रखना शुरू कर दें। इससे आपको आस्टियोपोरोसिस होने की आशंका कम होगी।

लड़कियां कर सकती हैं अस्थि घनत्व को कंट्रोल

हड्डियां कमजोर होने की समस्या ज्यादातर 45-50 उम्र की महिलाओं में दिखाई देती है। हालांकि आजकल लड़कियां 30 की उम्र के बाद भी इसका शिकार हो रही हैं। मगर आप सही लाइफ स्टाइल को अपनाकर इसके खतरे को कम कर सकती हैं। इसके लिए सही डाइट के साथ व्यायाम, ब्रेकफास्ट करना, ज्यादा देर एक ही सीट पर न बैठना जैसी अच्छी आदतों को अपनाएं।

30 की उम्र के बाद जरूरी है जांच

30-35 की उम्र के बाद या मनोपॉज की स्थिति के बाद महिलाओं को आस्टियोपोरोसिस व बोन डेंसिटी टेस्ट करवाते रहना चाहिए। वहीं युवा लड़कियों को इसकी जांच करवाने की सलाह तब दी जाती है, जब उनकी हड्डियां आसानी से टूटने लगे। बोन डेंसिटी टेस्ट डीएक्सए मशीन पर किया जाता है, लेकिन जांच इस आधार पर की जाती है कि आप कोई दवाई तो नहीं ले रहीं।

एस्ट्रोजन थैरेपी से करें इलाज

महिलाओं को इस स्थिति में एस्ट्रोजन थैरेपी यानी ईटी करवाने की सलाह दी जाती है, लेकिन कई बार एस्ट्रोजन को प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन थैरेपी यानी एचटी के साथ मिलाकर भी दिया जाता है। यह थैरेपी मनोपॉज के लक्षणों को कंट्रोल करके हड्डियों को होने वाले नुकसान से बचाती है।

मजबूत हड्डियों के लिए डाइट :

अंडे

प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्ज से भरपूर अंडे का सेवन भी हड्डियों का मजबूत बनाता है। आप ब्रेकफास्ट में उबला अंडा या ऑमलेट शामिल कर सकते हैं।

दूध

ब्रेकफास्ट में दूध जरूर लें। इसमें कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, फास्फोरस और पोटाशियम होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है।

नट्स

बादाम और मूंगफली, अखरोट में कैल्शियम, प्रोटीन के साथ ओमेगा-3 भी होता है, जो हड्डियों को मजबूत करता है।

हरी सब्जियां

अपनी डाइट में पालक, मेथी, गोभी और ब्रोकली जैसी हरी सब्जियां जरूर शामिल करें। यह शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करके हड्डियों को मजबूत बनाएंगी।

केला

इसमें पोटाशियम, कैल्शियम और मैगनीशियम होते हैं। ये तीनों पोषक तत्त्व हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। स्वस्थ जीवनशैली इस बीमारी के खतरे को कम कर सकती है।

दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर प्रत्यक्षियों ने प्रचार की पकडी रफ्तार

राजनाथ सिंह,पीएम मोदी,नड्डा समेत केजरीवाल तक उतरें रण में झोंक दी ताकत

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। एसडी सेठी।दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर छठे चरण के तहत शनिवार 25 मई को मतदान होने जा रहा है। राजधानी दिल्ली में इस वक्त 44 से 45 के तापमान ने मतदाताओ को घरो में छिपने को मजबूर कर दिया है। पर तमाम उम्मीदवारों ने भी बढे हुए पारे को ठेंगा दिखाते हुए अपने -अपने क्षेत्रों में रोड शो,पद यात्राओ के सिलसिले में सुबह -सवेरे ही 5 बजे पार्को, जिम आदि में पहुंचकर मतदाताओ से संवाद,मेल मिलाप शुरू कर दिया है। इसी कडी में नोर्थ-ईस्ट सीट से भाजपा प्रत्यक्षी मनोज तिवारी के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शौ निकाला और रैली को भी संबोधित किया। इस सीट से मुख्य मुकाबला कांग्रेस+आप के संयुक्त प्रत्यक्षी कन्हैया कुमार के अलावा दो बार के सांसद रहे बैकुंठ लाल शर्मा प्रेम की बेटी निवेदिता शर्मा प्रेम भी दोनों को टक्कर दे रही है। वह राष्ट्रीय जनलोक पार्टी सत्य (आरजेपी) की और से चारपाई के निशान पर चुनाव लड रही है।

निवेदिता शर्मा डोर टू डोर लोगों से संपर्क कर रही है।उनकी टीम में क्षत्रीय समाज, राजपूत समाज के साथ पंजाबी समाज के बडी संख्या में लोग जुटे हुए है। हालांकि निवेदिता शर्मा भाजपा की ही अधिकारी है। बावजूद इसके वह भाजपा के मनोज तिवारी को ही नुकसान पहुंचा रही है। सोमवार को उस्मान पुर चौथे पुस्ते पर कांग्रेस+आप के संयुक्त उम्मीदवार कन्हैया कुमार को एक शख्स माला पहनाने के बहाने आया उनके मुंह पर काली स्याही फेंकी और थप्पड जड दिए। पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया । पर बुद्धवार को कोर्ट से बेल पर छूटकर आ गया।

दिल्ली के सबसे बडे लोकसभा क्षेत्र नोर्थ वेस्ट की रिजर्व सीट से मैदान में मुख्य मुकाबला भाजपा के योगेन्द्र चंदौलिया और कांग्रेस+ आप के संयुक्त उम्मीदवार उदित राज के बीच है। हालांकि उदित राज 2014 में बीजेपी से चुनाव लड़ थे लेकिन अब वो कांगेस पार्टी में है। मतदाताओ में उदित राज को लेकर बेहद गुस्सा दिखाई दे रहा है। इसलिए भी भाजपा के कैंडीडेट योगेन्द्र चंदौलिया का पलडा भारी दिखाई देता है। मंगलवार को योगेन्द्र चंदौलिया के समर्थन में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रोड किया। रैली भी की। रोड शो के दौरान सडक के दोनो ओर लोग हाथों में भाजपा के झंडे थामे नारे लगाते हुए नगाड़े की थाप पर नाचते दिखाई दिए । इस मौके भाजपा मंडल अध्यक्ष उमेश गिरी ,पूर्व पार्षद मनीष चौधरी, मंडल महिला मोर्चा अध्यक्ष डिंपल चावला, प्रवीण गुप्ता,राजेंद्र भाटिया समेत हजारों लोगों की अपार भीड के जन समर्थन से भाजपा उम्मीदवार योगेन्द्र चंदौलिया की जीत की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं वेस्ट दिल्ली से भाजपा प्रत्यक्षी कमलजीत सहरावत और आप के महाबल मिश्रा के के बीच टक्कर है। बुद्धवार को भाजपा प्रत्यक्षी कमलजीत सहरावत के समर्थन मे पीएम नरेंद्र मोदी ने द्वारका सेक्टर-14 स्थित वेगास मॉल के सामने डीडीए पार्क में बडी रैली की रैली में हजारों की संख्या में महिला-पुरूषों की मौजूदगी से इस सीट पर भाजपा प्रत्यक्षी का पलडा भारी दिखाई दे रहा है। कमलजीत सहरावत दिल्ली की पूर्व मेयर रही हैं। वहीं द्वारका बी से पार्षद रही हैं, इसके अलावा सोशल वर्कर्स भी है। वहीं दूसरी ओर मुकाबले में आप +कांग्रेस के संयुक्त प्रत्यक्षी महाबल मिश्रा है। मिश्रा द्वारका सीट से विधायक है। निगेटिव सेंटीमेंट नहीं है। जन सुलभ नेता की छवी है। इसके अलावा न ई दिल्ली सीट से भाजपा की बांसुरी स्वराज का मुकाबला आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती से है। भारतीय वर्तमान में विधायक है। इनके खिलाफ पत्नी के उत्पीडन का मामला दर्ज है। वहीं बांसुरी सुषमा स्वराज की बेटी है। चांदनी चौंक सीट से व्यापार मंडल से भाजपा के प्रवीण खंडेलवाल का मुकाबला कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल से है। यहां से 2019 में भाजपा के हर्षवर्धन सांसद चुने गए थे। इस बार मुकाबला खासा कडा बताया जा रहा है। दक्षिण दिल्ली से भाजपा के रामवीर सिंह विधूडी और आप + कांग्रेस के सही राम पहलवान के बीच तगडा मुकाबला है ।यहां से भी बीजेपी कैंडीडेट राम वीर सिंह विधूडी पहलवान को पटखनी देते दिखाई दे रहे है। वहीं पूर्वी दिल्ली से भाजपा से हर्ष मल्होत्रा और आप+ कांग्रेस के कुलदीप कुमार के बीच कांटे की टक्कर है। पर आम आदमी पार्टी के मुखिया, सीएम और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत सत्येंद्र जैन के अलावा आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास पर मारपीट और बदसलूकी के मामले में पी एस की गिरफ्तारी ने आप पार्टी का माहौल बिगाड दिया है। इसी के मद्देनजर मतदाताओ का रूझान बीजेपी की तरफ मुड गया है। इससे साबित होता है कि भाजपा दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर जीत की खुमारी अभी से दिखाई देने लगी है।4 जून को परिणाम घोषित होने पर सभी दलों की असलियत सामने आ जाएगी।

क्या इन्ही निम्नलिखित घोटालों की बात कह गए थे अमित शाह

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के घोटालों को जनता के समक्ष खोलने से क्या जनता को कोई फर्क पड़ेगा, उम्मीद कम है क्योंकि सभी राजनैतिक दल के नेता एक दूसरे पर ये आरोप प्रत्यारोप लगाते ही रहते हैं, फिर आम आदमी पार्टी ने ऐसा किया तो क्या नया है, बड़ा सवाल ?,

1. 2,875 करोड़ का शराब घोटाला,
2. 78 हजार करोड़ का जल बोर्ड का घोटाला,
3. 5 हजार करोड़ का क्लास रूम निर्माण का घोटाला,
4. 1 हजार करोड़ का नकली दवाईयों का घोटाला,
5. 4 हजार करोड़ का लैब एक्स-रे घोटाला,
6. 1,850 करोड़ का गाड़ियों में पैनिक बटन का घोटाला
7. 1 हजार करोड़ का बस खरीदी में घोटाला,
8. उग्रवादी संगठन द्वारा विडियो के माध्यम से उजागर लिया गया फंड
9. 125 करोड़ का शीशमहल...
10. बसों में सीसीटीवी घोटाला
11. महिला फ्री के नाम पर चला रखा पिंक पास की पेमेंट का घोटाला

और

राजनीतिक गलियारों में दिल्ली में कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार के लिए वोट की मांग और पंजाब में उसी कांग्रेस पार्टी और उसके उम्मीदवारों पर विरोधाभाषी बयान?

बीजेपी का दावा अन्य राजनीतिक दलों के बयानों पर दावा किया है और साथ ही इसकी सत्यता को जांचने के लिए कहा है की आप इसे गूगल से सत्यापित कर सकते हैं। जाने क्या कहा अपने इस दावे में

1. 2014 में मेडिकल कॉलेज - 387, 2024 में मेडिकल कॉलेज - 660
2. 2014 में एम्स की संख्या - 7, 2024 में एम्स की संख्या- 22
3. 2014 में जीडीपी - 1.8 ट्रिलियन, 2024 में जीडीपी - 3.7 ट्रिलियन
4. 2014 में निर्यात - 200 बिलियन, 2024 में निर्यात - 759 बिलियन
5. 2014 में मेट्रो सिटी - 5, 2024 में मेट्रो सिटी - 20
6. 2014 में हवाई अड्डे - 74, 2024 में हवाई अड्डा - 152
7. 2014 में ग्रामीण विद्युतीकरण प्रवेश - 40%, 2024 में ग्रामीण विद्युतीकरण कवरेज - 95%
8. 2014 में एक्सप्रेसवे की लंबाई - 680 किमी, 2024 में एक्सप्रेसवे की लंबाई - 4067 किमी
9. 2014 में सड़क गुणवत्ता - 80वीं रैंक, 2024 में सड़क गुणवत्ता- 42वीं रैंक
10. 2014 में कुल यूनिकॉर्न - 1, 2024 में कुल यूनिकॉर्न - 114
11. 2014 में 1GB डेटा - 200 रुपये, 2024 में 1GB डेटा- 15 रुपये
12. 2014 में रेल की लंबाई - 22048 किलोमीटर, 2024 में रेल की लंबाई - 55198 किमी
13. 2014 में इंटरनेट कनेक्शन - 25%, 2024 में इंटरनेट कनेक्शन - 93%
14. 2014 में एमबीबीएस सीटें - 51,348, 2024 में एमबीबीएस सीटें - 101,148
15. 2014 में पीजी मेडिकल सीटें - 31,152, 2024 में पीजी मेडिकल सीटें - 65,335

अधिक सामानः

A. 80 करोड़ के लिए गरीब कल्याण राशन,
B. सभी के लिए जल जीवन, साफ पानी, जन औषधि पीएम आवास योजना...
C. कोई बड़ा आतंकवादी हमला नहीं,
D. विदेशी धरती पर भारत के दुश्मन मारे गए...
E. यूपीआई पेमेंट,
F. वंदे भारत आदि.
G. दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम
H. दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति
I. विश्व का सबसे लम्बा रेलवे स्टेशन
J. एशिया की सबसे बड़ी हेलीकाप्टर निर्माण इकाई...
K. विश्व की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग
L. अयोध्या में राम मंदिर और
M. धारा 370 को हटाना

रूस, यूक्रेन, ईरान, युद्ध के समय मे भी पेट्रोल उत्पादक देशो से क्रूड आयल प्रोडक्शन बढाऐ

जांचे क्या यह दावे सही है या सिर्फ सत्ता को पाने के लिए किए जा रहे हैं जनता के बीच

रितु झालानी को जयहिंद नेशनल पार्टी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किया

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। भारत के हर वर्ग के व्यक्ति के साथ काम करने के लिए और एक नई सोच के साथ युवाओं, महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ने के लिए जयहिंद नेशनल पार्टी का गठन आज से 4 वर्ष पूर्व नेता जी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों पर चलने के लिये किया गया था । इसी कड़ी में दिल्ली के सिविल लाइंस में जयहिंद नेशनल पार्टी द्वारा आदर्श श्रीवास्तव को राष्ट्रीय महासचिव बनाने के लिए पदभार ग्रहण समारोह आयोजित किया गया ।

रितु झालानी को जयहिंद नेशनल पार्टी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किया।

इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डॉ आशीष श्रीवास्तव , राष्ट्रीय अध्यक्ष, जयहिंद नेशनल पार्टी ने डॉ. राजीव मिश्रा - राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सांसद प्रत्याशी गौतमबुद्धनगर लोकसभा, आदर्श श्रीवास्तव , राष्ट्रीय महासचिव , रितु झालानी - भावी विधायक प्रत्याशी दिल्ली प्रदेश, आकाश श्रीवास्तव सांसद प्रत्याशी उत्तरपूर्वी लोकसभा दिल्ली, सीए सागर हुड्डा -भावी विधायक प्रत्याशी दिल्ली प्रदेश, एडवोकेट श्री बलदेव राज सचदेवा, डॉ. हिमांशु भटनागर सांसद प्रत्याशी मेरठ-हापुड़ लोकसभा , प्रिंस श्रीवास्तव और अन्य कई पार्टी के पदाधिकारी एवं पूरा झालानी परिवार मौजूद रहा। वहाँ मौजूदा अतिथिगण का फूलमाला और अंगवस्त्र से स्वागत किया गया।

कार्यक्रम में जयहिंद नेशनल पार्टी के अध्यक्ष , उपाध्यक्ष और वरिष्ठ लोगों द्वारा आदर्श श्रीवास्तव को औपचारिक तौर से पत्र देकर पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया।

इस मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह भी घोषणा की कि जयहिंद नेशनल पार्टी आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में मजबूती से सभी 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी।

डॉ.राजीव मिश्रा- राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने बताया कि जयहिंद नेशनल पार्टी एक राजनीतिक दल है, जिसका गठन 1 जुलाई 2020 में हुआ था, इसका हैशटैग #भले_लोगों_की_पार्टी हैं . जयहिंद नेशनल पार्टी भारत के युवा पीढ़ी को सही दिशा देने के लिए , वृद्ध लोगों को सहारा देने के लिए , महिलाओं एवं सभी वर्ग के लोगों के साथ काम करने और उन्हें देशहित, राष्ट्रहित, समाजहित के लिये अपने संगठन में जोड़ने का काम करती है। पार्टी का चुनाव चिन्ह बाँसुरी हैं।

नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय नागरिकों और निवासियों को निम्नलिखित के प्रति सचेत करता हैः

नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय नागरिकों और निवासियों को निम्नलिखित के प्रति सचेत करता हैः

आने वाले दिनों में 47 से 55 डिग्री सेल्सियस के बीच बढ़ते तापमान और क्यूम्यलस बादलों की उपस्थिति के कारण अधिकांश क्षेत्रों में दमघोंटू माहौल होने के कारण, यहां कुछ चेतावनियां और सावधानियां दी गई हैं...

कारों को साफ़ किया जाना चाहिएः

1. गैस सामग्री.
2. लाइटर.
3. कार्बोनेटेड पेय पदार्थ।
4. सामान्यतः इत्र और उपकरण बैटरियाँ।
5. कार की खिड़कियाँ थोड़ी खुली (वेंटिलेशन) होनी चाहिए।
6. कार के फ्यूल टैंक को पूरा न भरें.
7. शाम के समय कार में ईंधन भरें।
8. सुबह के समय कार से यात्रा करने से बचें.
9. कार के टायरों को ज़्यादा न भरें, ख़ासकर यात्रा के दौरान।

बिच्छुओं और सांपों से सावधान रहें क्योंकि वे अपने बिलों से बाहर निकलेंगे और ठंडी जगहों की तलाश में खेतों और घरों में प्रवेश कर सकते हैं।

खूब पानी और तरल पदार्थ पियें।

सुनिश्चित करें कि गैस सिलेंडर को धूप में न रखें।

सुनिश्चित करें कि बिजली मीटरों पर अधिक भार न डालें और एयर कंडीशनर का उपयोग केवल घर के व्यस्त क्षेत्रों में करें, विशेषकर अत्यधिक गर्मी के समय में।

सूरज की रोशनी के सीधे संपर्क में आने से बचें, खासकर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच।

अंत मेंः कृपया इस जानकारी को साझा करें क्योंकि अन्य लोग नहीं जानते होंगे और हो सकता है कि वे इसे पहली बार पढ़ रहे हों...

सादर, नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय

1 जून से नाबालिग के गाडी चलाने पर , 25000 जुर्माना, रजिस्ट्रेशन रद्द के साथ पेरेंट्स पर कारवाई

परिवहन विशेष न्यूज

एसडी सेठी। देशभर में फॉर व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ट्रांसपोर्ट अथॉरटी दफ्तरों में चक्कर कटाई से छुटकारा मिलने जा रहा है। 01 जून से नया ड्राइविंग लाइसेंस नियम लागू हो जाएगा ।इसके बाद नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया बेहद आसान हो जाएगी। साथ ही नाबालिगों द्वारा गाडी चलाते पाए जाने पर माता-पिता के खिलाफ कारवाई के अलावा 25000 रूपये का जुर्माना के अलावा गाडी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी रद्द कर दिया जाएगा ।सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में नियमों में बडे बदलाव किए है। जिससे ड्राइवर का लाइसेंस प्राप्त करने की प्रकिया बहुत सरल हो जाएगी। दरअसल नए नियम में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने होगे। नए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों आरटीओ में टेस्ट देने की मौजूदा बाध्यता खत्म हो जाएगी।

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले के पास अपनी पसंद के निकटतम केंद्र पर ड्राइविंग टेस्ट देने का विकल्प होगा ।सरकार प्राईवेट प्लेयर को ड्राइविंग टेस्ट लेने के लिए अधिकृत करते हुए प्रमाणपत्र जारी करेगी। बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने पर भारी जुर्माना लगेगा ।इसे बढाकर 1000 रूपये से 2000 रूपये तक किया जाएगा ।इसके अलावा अगर कोई नाबालिग वाहन चलाता हुआ पाया गया तो उसके माता-पिता के खिलाफ कारवाई की जाएगी। साथ ही 25000 रूपये का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। गाडी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कैंसिल कर दिया जाएगा। वहीं ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज को भी सरल बनाया जाएगा ।यानि मंत्रालय पहले से ही आवेदकों को लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में पहले से सूचित करेगा ।जिन्हे वह प्राप्त करना चाहते हैं।

प्राईवेट ड्राइविंग स्कूल खोलने वाले के पास न्यूनतम 1 एकड भूमि वहीं [फॉर व्हीलर] वाहन प्रशिक्षण के लिए 2 एकड भूमि होनी चाहिए। इसके अलावा स्कूलों को उपयुक्त परीक्षण प्रदान करनी होगी। वही प्रशिक्षकों के पास हाई स्कूल डिप्लोमा या/ समकक्ष कम से कम 5 साल ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए और बायोमेट्रिक और आईटी सिस्टम से परिचित होना चाहिए। हल्के मोटर वाहन 4 सप्ताह में 29 घंटे,8 घंटे थ्योरी 21 घंटे प्रेक्टिकल के होगे। वहीं भारी मोटर वाहन 6 सप्ताह में 38 घंटे,8 घंटे थ्योरी,और 31 घंटे प्रैक्टिकल में विभाजित होगें।

महिला वैज्ञानिक की सड़क हादसे में हुई थी मौत, मां को मिलेगा 94 लाख रुपये का मुआवजा

गुरुग्राम। करीब सात साल पहले खेड़कीदौला गांव के पास ट्रक की चपेट में आने से हुई वरिष्ठ महिला वैज्ञानिक की मौत के मामले में मृतक की मां को 94.94 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। यह मुआवजा राशि छह प्रतिशत की दर से दी जाएगी। यह आदेश मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल तरुण सिंगल ने दिया है। मृतक अंजू जैन (44) राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो पूसा परिसर,दिल्ली में वरिष्ठ वैज्ञानिक थी। उनकी मां उत्तर प्रदेश के जिला बड़ौत के पठानकोट-1 निवासी कृष्णा रानी जैन ने ने अदालत में याचिका दायर कर चार करोड़ रुपये की मांग की थी।

दिसंबर 2016 को हुआ था हादसा

खेड़कीदौला थाना पुलिस को दी गई शिकायत में महेंद्र सिंह ने बताया कि वह राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो में वैज्ञानिक नियुक्त है। 17 दिसंबर 2016 को वह अंजू जैन के साथ अपनी गाड़ी से मेहंदीपुर बालाजी जा रहे थे।

दोपहर करीब साढ़े चार बजे वह जब खेड़कीदौला गांव के पास पहुंचे तो उनके सामने चल रहे ट्रक ने अचानक से तेज रफ्तार में ट्रक को एक साइड से दूसरी साइड में ले आया। इसके चलते उनकी गाड़ी का आगे का हिस्सा ट्रक के पीछे हिस्से से भिड़ गया था। उन्होंने बताया कि हादसे में वह दोनों घायल हो गए थे। उन्होंने अंजु जैन को प्राइवेट अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया,जहां पर डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

हादसे के समय ट्रक गुरुग्राम के बार गुर्जर निवासी बीर सिंह ट्रक चला रहा था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि वह बीमा कंपनी यह साबित करने में सफल हो गई कि ट्रक बीमा नियमों के विरुद्ध चलाया जा रहा था। इसके साथ ही चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। यह राशि चालक की तरफ से दी जाएगी। पहले यह राशि बीमा कंपनी याचिकाकर्ता को देगी। इसके बाद यह राशि ट्रक चालक से वसूली जाएगी।

अगर कोई अनजाना भेजता है लिंक तो हो जाएं सावधान, एक क्लिक से रिटायर्ड इंजीनियर ने गंवाए 41 लाख

गुरुग्राम। साइबर ठगों ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर गुरुग्राम के सेक्टर 10 निवासी रिटायर्ड इंजीनियर से 41 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना वेस्ट पुलिस ने बुधवार को केस दर्ज कर लिया है।

इंटरनेट पर निवेश के लिए देखा था विज्ञापन

सेक्टर 10 निवासी सुमित कुमार मलिक ने साइबर पुलिस को दी शिकायत में कहा कि बीते दिनों उन्होंने इंटरनेट पर एक विज्ञापन देखा।

इसमें शेयर बाजार में निवेश कर आनलाइन ट्रेडिंग कर लाभ कमाने के लिए बताया गया था। इसके बाद साइबर ठगों ने उनके वाट्सएप पर एक लिंक भेज दिया गया। रिटायर्ड इंजीनियर के मोबाइल में एक शेयर खरीदने वाला एप डाउनलोड कराया। इसके बाद उनसे शेयर खरीदने के लिए कहा।

ग्रेटर नोएडा में बिजली कटौती से परेशान लोग पहुंच गए थाने, दो रात से कार में रात बिताने को थे मजबूर

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के श्री राधा स्काई गार्डन सोसायटी (श्री राधा स्काई गार्डन सोसायटी) के लोगों ने बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज कराने की लिखित शिकायत दी। दरअसल लोगों का आरोप है कि बिल्डर ने खरीदारों से बिजली ढांचे को पूरा करने के लिए एडवांस में पैसा लिया हुआ है। इसके बाद भी लोगों की संख्या के हिसाब से बैकअप क्षमता आधी है।

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा। भीषण गर्मी के सितम के बीच लोगों को बिजली कटौती का भी सामना करना पड़ रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट (Greater Noida West) में बिजली संकट कम नहीं हो रहा है।

पिछले तीन दिनों में यह समस्या और गंभीर होती जा रही है। लोगों को बिजली कंपनी के प्रबंधन से निराशा हाथ लग रही है।

बिजली कटौती से परेशान लोग पहुंचे कोतवाली

मंगलवार की देर रात बिजली कटने के दौरान प्रबंधन की ओर से बैकअप नहीं मिलने से नाराज श्री राधा स्काई गार्डन सोसायटी (Shri Radha Sky Garden Society) के निवासी देर रात बिसरख कोतवाली पहुंचे। प्रबंधन पर क्षमता के अनुसार पावर बैकअप के लिए डीजी (डीजल जनरेटर) नहीं होने लिखित शिकायत की बिसरख पुलिस को दी है।

गौरव पटेल एवं समीर कपूर ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से श्री राधा स्काई गार्डन सोसायटी में बिजली एवं डीजल जेनरेटर बैकअप की भारी किल्लत है। एनपीसीएल की बिजली हर रोज ठप हो रही है। इस दौरान प्रबंधन के डीजी सेट से बैकअप भी नहीं मिल पाता है।

बिल्डर पर केस दर्ज कराने के लिए की शिकायत

श्री राधा स्काई गार्डन सोसायटी के लोगों ने बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज कराने की लिखित शिकायत दी। दरअसल लोगों का आरोप है कि बिल्डर ने खरीदारों से बिजली ढांचे को पूरा करने के लिए एडवांस में पैसा लिया हुआ है। इसके बाद भी लोगों की संख्या के हिसाब से बैकअप क्षमता आधी है।

बिजली कटौती होने पर डीजी सेट भार नहीं झेल पा रहा है। बिल्डर की ओर से अतिरिक्त डीजी सेट लगाए नहीं गए हैं। बिजली कटते ही सोसायटी अंधेरे में डूब जाती है। बिल्डर की ओर से दिसंबर 2023 तक बिजली के ढांचे में सुधार का समय दिया। एक साल

बाद भी स्थिति जस की तस है। बिल्डर ने बिजली के ढांचे में सुधार नहीं किया।

दो रात से पार्क और कार में गुजारी रात

बीते तीन दिनों से श्री राधा स्काई गार्डन सोसायटी के निवासी बिजली समस्या से परेशानी हैं। दो रात बिजली गुल रहने से यहां के निवासियों ने पार्क और कार में रात गुजारी। भीषण गर्मी में यहां पर बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

पानी का काला कारोबार, अवैध भूजल दोहन से सूख रही धरती की कोख

परिवहन विशेष न्यूज

जल ही जीवन है लेकिन अब लोगों को जीवन देने वाला जल व्यापार में बदल गया है। बात व्यापार में बदलने तक ही सीमित नहीं रही। अब इसका धंधा करने वाले लोग रुपया कमाने के लालच में इस कदर अंधे हो गए हैं कि वह लोगों को पानी के नाम पर बीमारियां बांट रहे हैं। गाजियाबाद में पानी के खारेपन की समस्या कुछ लोगों के लिए वरदान बन गई है।

गाजियाबाद। जल ही जीवन है, लेकिन अब लोगों को जीवन देने वाला जल व्यापार में बदल गया है। बात व्यापार में बदलने तक ही सीमित नहीं रही। अब इसका धंधा करने वाले लोग रुपया कमाने के लालच में इस कदर अंधे हो गए हैं कि वह लोगों को पानी के नाम पर बीमारियां बांट रहे हैं। सीधे सबमर्सीबल से निकाले जाने वाले जल का खारापन दूर करने के लिए इस धंधे में उतरे लोग पानी में केमिकल मिलाकर खुलेआम बेच रहे हैं और शहर की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। पेश है शाहनवाज अली की रिपोर्ट।

गाजियाबादः क्षेत्र में पानी के खारेपन की समस्या कुछ लोगों के लिए वरदान बन गई है। नगर निगम और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अभी तक अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छ जल मुहैया नहीं करा पाया है। यही वजह है कि जिले में करीब एक हजार लोग गली-मोहल्लों में आरओ प्लांट के नाम पर प्रतिदिन अवैध रूप से करोड़ों लीटर भूजल दोहन कर रहे हैं, जो घर-घर और दफ्तर व समारोह में बोतल और केंटर से मनमाने दामों में शुद्ध जल के नाम पर मानकों के विपरीत जलापूर्ति कर रहे हैं।

जिले में शहरी क्षेत्र में एक हजार से अधिक अवैध आरओ प्लांट गली-मोहल्लों में संचालित हो रहे हैं। शहर के विजय नगर, सिद्धार्थ विहार, गोविंदपुरम, पटेल नगर, संजय नगर, घंटाघर, कैला भट्ठा, चिरंजीव विहार के अलावा खोड़ा, साहिबाबाद, हिंडन विहार, पसौंडा, शालीमार गार्डन, लोनी आदि में एक हजार से अधिक आरओ प्लांट संचालित हो रहे हैं।

कमाल की बात किसी एक आरओ प्लांट के पास लघु सिंचाई विभाग की ओर से कोई एनओसी है न लाइसेंस। शहरी क्षेत्र के गली-मोहल्लों में आरओ प्लांट लगाकर पानी जांच कराए बिना 20-20 लीटर की बोतल और 200 से 500 लीटर के टैंकों में भरकर सप्लाई की जा रही है। भूजल दोहन पर प्रतिबंध के बावजूद रोजाना 25 से 30 करोड़ लीटर से अधिक अवैध रूप से भूजल किया जा रहा है। रोक के बावजूद जगह-जगह सबमर्सिबल लगे हैं, जिससे दिनोंदिन धरती की कोख सूख रही है।

हर साल करीब आठ फुट नीचे जा रहा भूजल स्तर

वर्ष 2018 - वर्ष 2024

- **विजयनगर क्षेत्र**

180 फुट - 200 फुट से अधिक

- **वैशाली, वसुंधरा और इंदिरापुरम**

120 से 150 फुट - 200 फुट से अधिक

- **दिल्ली गेट, नंदग्राम, घंटाघर**

200 फुट - 300 फुट तक

- **लोनी क्षेत्र**

75 फुट - 100 से 200 फुट

- **मुरादनगर और मोदीनगर**

100 फुट - 150 फुट से अधिक

औद्योगिक इकाइयों का सर्वे

तेजी से गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए निर्देश दे चुके हैं। यही वजह रही कि कई-कई वर्षों से धरती का सीना चीरकर अवैध भूजल दोहन कर रहीं 30 हजार से अधिक छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाइयों का जिला भूगर्भ प्रबंधन समिति ने सर्वे शुरू किया था, जो लोकसभा चुनाव के दौरान थम गया। सर्वे में लोनी, ट्रॉनिका सिटी, रूपनगर, बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकांश इकाइयों में अवैध भूजल दोहन होता हुआ मिला, जिनकी सूची तैयार की गई।

ग्रेटर नोएडा में घर बनाने का मौका, यमुना अथॉरिटी ला रही आवासीय प्लॉट योजना

नोएडा एयरपोर्ट के पास अपना आशियाना बनाने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए गुड न्यूज आई है। यमुना प्राधिकरण जल्द छोटे आकार के आवासीय प्लॉट की योजना निकालेगा। इसके साथ ही योजना में बड़े आकार के प्लॉट भी शामिल होंगे। योजना में चार हजार प्लॉट शामिल होने की संभावना है।

नोएडा। यमुना प्राधिकरण एक बार फिर छोटे आकार के आवासीय प्लॉट की योजना निकालने जा रहा है। आचार संहिता समाप्त होने के बाद अगले माह में यह योजना निकाली जाएगी। इसके साथ ही योजना में बड़े आकार के प्लॉट भी शामिल होंगे।

सेक्टर 18, 20 में होंगे प्लॉट

यमुना प्राधिकरण में आवासीय संपत्ति की मांग साल दर साल बढ़ती जा रही है। इस मांग को पूरा करने के लिए प्राधिकरण ने एक बार फिर 60 व 90 वर्गमीटर के प्लॉट की योजना निकालने का फैसला किया है। योजना में चार हजार प्लॉट शामिल होने की संभावना है। हालांकि अभी प्लॉटों की संख्या अंतिम रूप से तय नहीं हुई है। यह प्लॉट सेक्टर 18, 20 में होंगे।

2018 में भी निकली थी छोटे आकार के प्लॉट की योजना

इससे पहले प्राधिकरण ने 2018 में छोटे आकार के प्लॉट की योजना निकाली थी। प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि छोटे आकार के प्लॉट की योजना से मध्य वर्ग की आवासीय जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्राधिकरण ने अधिकतर आवासीय प्लॉट योजना 120 वर्गमीटर से लेकर चार हजार वर्गमीटर तक के प्लॉटों की निकाली हैं। छोटे प्लॉटों के साथ प्राधिकरण तीन सौ वर्गमीटर से लेकर चार हजार वर्गमीटर के प्लॉट की योजना भी निकालेगा। इसमें 450 प्लॉट शामिल होने होने की संभावना है। प्राधिकरण ने चालू वित्त वर्ष में विभिन्न प्लॉट योजना से 1200 से 1300 करोड़ रुपये पंजीकरण राशि के रूप में जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

अगले माह ई नीलामी से होगा प्लॉटों का होगा आवंटन

यमुना प्राधिकरण ने लोकसभा चुनाव की आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले संस्थागत, कामर्शियल, फ्यूल स्टेशन, होटल, मैरिज होम आदि की प्लॉट योजना निकाली थी। चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण इन योजनाओं की ई नीलामी नहीं हो पाई है। प्राधिकरण ने जून में ई नीलामी का कार्यक्रम तय कर दिया है। सभी प्लॉटों का आवंटन ई नीलामी के आधार पर किया जाएगा।

स्वाति मालीवाल प्रकरण में छिपे गहरे सियासी मायने को ऐसे समझिए

कमलेश पांडे

भारतीय सियासत में विपक्षी दलों के बीच एक लंबी सियासी लकीर खींचने वाले अरविंद केजरीवाल के लिए स्वाति मालीवाल केस कोई नई चीज नहीं है। बस, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि पुराने साथियों के दुश्मन बन जाने का एक और नया मामला है जो समय के साथ पुराने मामलों की तरह दब जाएगा।

आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर 'आप' की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगाया है, वह बहुत गम्भीर बात है। लेकिन उससे भी गम्भीर बात यह है कि इस मामले में शुरू से अबतक जो भी घटनाक्रम प्रकाश में आया है, उसके पीछे किसी गहरे सियासी षड्यंत्र का भी हाथ हो सकता है! इसलिए इस पूरी घटना के परिप्रेक्ष्य में छिपे सियासी मायने को समझना बहुत जरूरी है।

अंतरिम जमानत पर तिहाड़ जेल से मुख्यमंत्री आवास पहुंचे अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचीं स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री के घर पर वैभव कुमार के इशारे पर या उनकी भागीदारी से या फिर दोनों तरह से जो कुछ भी हुआ, वह अप्रत्याशित था। लेकिन, उसकी बौखलाहट में दिल्ली पुलिस को फोन करके स्वाति मालीवाल बुरी तरह से घिर गईं। ऐसा इसलिए कि इस मामले में एफआईआर करवाने से पहले पार्टी के स्तर पर उन्होंने घटनाक्रम के डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, जिसमें राज्यसभा सांसद संजय सिंह का भी उन्हें प्रारंभिक साथ मिला। परंतु उनके सारे प्रयास जब विफल हो गए, तब उन्होंने इस मामले में एफआईआर दी। जिसके बाद पूरी आप पार्टी ही उनके खिलाफ हो गई। उनके लिए सुकून की बात यह है कि भाजपा ने उनके मुद्दे को तूल दे दिया और उपराज्यपाल वी के सक्सेना तक ने उनसे हमदर्दी जताई। इससे आप पार्टी के इन आरोपों को बल मिला कि अब वह बीजेपी की एजेंट बन चुकी हैं।

ऐसे में सीधा सवाल यही उठता है कि अरविंद केजरीवाल के सियासी दोस्तों ने उनसे दुश्मनी तो बहुत साधी, लेकिन वो प्रायः बेअसर ही रही है। क्योंकि स्वाति मालीवाल से पहले भी अरविंद केजरीवाल के कई राजनैतिक दोस्त उनको आरोपों के कठघरे में खड़ा कर चुके हैं, जिनमें कपिल मिश्रा से लेकर कुमार विश्वास तक का नाम शुमार किया जाता है। बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक सेहत विशेष रूप से प्रभावित नहीं हुई है। वहीं कड़वा सच यह भी है कि दुश्मन की तरह पेश आ रहे अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी कोई खास मुकाम हासिल नहीं कर पाये। यदि किरण बेदी, अन्ना हजारे और जनरल वी के सिंह की बात छोड़ दी जाए तो। ऐसे में यही बात सामने आ रही है कि बहुचर्चित स्वाति मालीवाल प्रकरण से मौजूदा संसदीय चुनाव में चाहे जो भी राजनीतिक नुकसान हो, लेकिन स्वाति मालीवाल केस का अरविंद केजरीवाल की सियासत पर बहुत ज्यादा असर होगा, ऐसा तो मुझे नहीं लगता।

आपने देखा होगा कि दिल्ली के 7 लोकसभा क्षेत्रों से लेकर पंजाब के 14 लोकसभा क्षेत्रों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का धुआंधार कैंपेन चल रहा है। कभी मीडिया के जरिये, तो कभी सोशल मीडिया के माध्यम से निरंतर वो अपनी बात कह रहे हैं और अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ भी लगातार रोड शो कर रहे हैं। इसी बीच वो नये नये नारे भी गढ़ रहे हैं, जिससे स्वाति मालीवाल से जुड़े सियासी हमले निष्प्रभावी दिखाई दे रहे हैं। हां, इतना जरूर है कि स्वाति मालीवाल केस के लेकर दिल्ली पुलिस की टीम पूरी तरह से सक्रिय है और उनके पीए विभव कुमार की गिरफ्तारी ने उन्हें अंदर से हिलाकर रख दिया है। ऐसा इसलिए कि पीए किसी भी व्यक्ति का वह राजदार होता है, जिसका अचानक चला जाना या किसी षड्यंत्र के तहत उसके बॉस से उसे अलग कर दिया जाना, ऐसी क्षति होती है, जिसकी त्वरित भरपाई किसी भी व्यक्ति के लिए मुश्किल होती है। इसलिए अरविंद केजरीवाल पर इस पूरे घटनाक्रम का तात्कालिक और दीर्घकालिक, दोनों प्रभाव पड़ेगा।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आप नेत्री सुनीता केजरीवाल के साथ रोड शो के दौरान बीजेपी के एक नारे को थोड़ा और विस्तार देते हुए कटाक्ष किया कि, 'अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं।' इतना ही नहीं, भले वो अंतरिम जमानत पर हैं और आगामी 2 जून को तिहाड़ जेल में उन्हें फिर से सरेंडर करना है। लेकिन चुनाव अभियान के दौरान वो खुद भी और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी लोगों को बार बार यह बात बताती रहती हैं कि यदि दिल्लीवालों ने 'इंडिया गठबंधन' के उम्मीदवारों को वोट देकर उनकी जीत पक्की कर दी तो अरविंद केजरीवाल को ज्यादा दिन के लिए जेल नहीं जाना पड़ेगा।

लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी समस्या स्वाति मालीवाल केस बन चुकी है, यह भी उन्हें समझना होगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पुराने साथियों में से एक और काफी निकटस्थ रहीं स्वाति मालीवाल अब उनकी नई विरोधी बन गई हैं। स्वाति मालीवाल ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री आवास पर उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने उन पर हमला किया। इस मामले में एफआईआर दर्ज होते ही दिल्ली पुलिस विभव कुमार को गिरफ्तार कर ले गई। जिसके बाद से वो पुलिस रिमांड पर हैं।

हालांकि, भारतीय सियासत में विपक्षी दलों के बीच एक लंबी सियासी लकीर खींचने वाले अरविंद केजरीवाल के लिए स्वाति मालीवाल केस कोई नई चीज नहीं है। बस, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि पुराने साथियों के दुश्मन बन जाने का एक और नया मामला है जो समय के साथ पुराने मामलों की तरह दब जाएगा। या फिर सवाल यह भी है कि यह मामला कहां तक जाएगा और अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर यह केस का कितना प्रभाव डालेगा, यह बदलता वक्त ही बताएगा, क्योंकि केंद्र में सत्ता परिवर्तन भले ही हो, किंतु अधिकारियों की मनोदशा बदलेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता? क्योंकि भारतीय प्रशासन और न्यायपालिका का यह निर्विवाद चरित्र रहा है कि जो भी एक बार कानूनी मकड़जाल में फंस गया वो फिर बाहर बमुश्किल ही निकल पाता है चाहे उसका राजनीतिक रसूख कुछ भी हो, कितना भी बड़ा हो। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव इसके दिलचस्प उदाहरण हैं।

इसलिए इतना तो कहा ही जा सकता है कि भले ही अपनी अचूक सियासी रणनीति के बल पर अरविंद केजरीवाल भविष्य में प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन जो विवाद उनके साथ जुड़ चुके हैं, वो उनकी राजनीति पर अपना कुप्रभाव अवश्य डालेंगे। स्वाति मालीवाल केस उनमें से एक है। इस केस ने अरविंद केजरीवाल को एकाएक ऐसा उलझा दिया है, जिसे सुलझाने के लिए उन्हें एक और विभव कुमार पैदा करना होगा। क्योंकि इस उलझन की सबसे बड़ी वजह उनके सहयोगी और करीबी विभव कुमार की गिरफ्तारी है। खास बात यह है कि स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर मुख्यमंत्री आवास पर मारपीट करने जैसा जो आरोप लगाया है, वह उत्तरप्रदेश के मायावती गेस्ट हाउस कांड की याद तरोताजा कर देता है।

राजनीतिक मामलों के जानकार बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए कभी अहम तो स्वाति मालीवाल भी रही हैं, लेकिन पीए विभव कुमार का

महत्व ऐसे भी समझा जा सकता है कि जेल जाने के बाद मुलाकात के लिए जेल प्रशासन को जिन मुलाकातियों की सूची दी गई, उसमें उनका भी नाम शामिल था। इसलिए उन्हें कमजोर करने के लिए विभव कुमार को भी फंसाना जरूरी था, जो अब ताजा विवाद के केंद्र में हैं! यहां पर मुश्किल यह है कि सिर्फ स्वाति मालीवाल ही नहीं, बल्कि संजय सिंह की बातों से भी लगता है कि कहीं न कहीं विभव कुमार ही दोषी हैं। वहीं, अरविंद केजरीवाल की एक भरोसेमंद कैबिनेट मंत्री आतिशी ने विभव कुमार को बेकसूर ठहराते हुए स्वाति मालीवाल पर ही बीजेपी के हाथों में खेलने का आरोप लगाया है, जिसकी अब कुछ कुछ पुष्टि बदलते घटनाक्रमों से भी होने लगी है।

इस पूरे प्रसंग में गौर करने वाली बात यह भी है कि पूरे विवाद में संजय सिंह एक अलग ही छोर पर दिखाई पड़ते हैं। जबकि अरविंद केजरीवाल के साथ विभव कुमार और संजय सिंह को सार्वजनिक रूप से आखिरी बार लखनऊ में देखा गया था। इससे स्पष्ट है कि विभव कुमार को साथ लखनऊ ले जाना भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया हुआ स्पष्ट संदेश ही था, जिस दौरान संजय सिंह का साथ होना भी बहुत मायने रखता है। कहना न होगा कि प्रवर्तन निदेशालय और अन्य जांच एजेंसियों के नोटिस की तरह विभव कुमार का मामला भी अरविंद केजरीवाल राजनीतिक रूप से ही लड़ रहे हैं। यही वजह है कि इस लड़ाई में अरविंद केजरीवाल की तरफ से मीडिया के सामने आ रहीं आतिशी भी स्वाति मालीवाल के टारगेट पर आ गई हैं, जिससे यह सियासी लड़ाई दिलचस्प बनती जा रही है।

सवाल यह भी है कि जब से मारपीट की यह घटना हुई है, स्वाति मालीवाल अपनी बात या तो पुलिस को बता रही हैं, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आमलोगों को बता रही हैं। उनका यहां तक कहना है कि 'दिल्ली के मंत्री झूठ फैला रहे हैं कि मुझ पर भ्रष्टाचार की एफआईआर हुई है, इसलिए बीजेपी के इशारे पर मैंने ये सब किया। यह एफआईआर 8 साल पहले 2016 में हो चुकी थी जिसके बाद मुझे सीएम और एलजी दोनों ने दो बार महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। क्योंकि यह केस पूरी तरह फर्जी है जिस पर डेढ़ साल से हाई कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है।'

BYD Seal ने केवल 3 महीनों में पार किया 1 हजार बुकिंग का आंकड़ा, जानिए फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

परिवहन विशेष न्यूज

BYD Seal भारत में चीनी EV निर्माता की तीसरी और सबसे महंगी इलेक्ट्रिक कार है। इस 3 वेरिएंट में पेश किया गया है। इसकी कीमत 53 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। BYD Seal EV को भारत में 5 मार्च को एक परफॉरमेंस इलेक्ट्रिक सेडान के रूप में लॉन्च किया गया था जिसकी रेंज एक बार चार्ज करने पर 650 किलोमीटर तक है।

नई दिल्ली। चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता BYD ने घोषणा की है कि भारत में इसकी तीसरी Electric Car ने लॉन्च के पहले तीन महीनों के अंदर 1000 से अधिक बुकिंग हासिल की हैं। इससे पहले ईवी निर्माता ने कहा था कि BYD Seal EV ने 15 दिनों के अंदर 500 बुकिंग हासिल की थीं।

BYD Seal में क्या खास?

BYD Seal भारत में चीनी EV निर्माता की तीसरी और सबसे महंगी इलेक्ट्रिक कार है। इस 3 वेरिएंट में पेश किया गया है। इसकी कीमत 53 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। BYD Seal EV को भारत में 5 मार्च को एक परफॉरमेंस इलेक्ट्रिक सेडान के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसकी रेंज एक बार चार्ज करने पर 650 किलोमीटर तक है।

ईवी निर्माता ने 7 किलोवाट का होम चार्जर और इंस्टॉलेशन सर्विस, 3 किलोवाट का पोर्टेबल चार्जिंग बॉक्स, BYD सील VTOL (वाहन से लोड तक) मोबाइल पावर सप्लाई यूनिट, 6 साल की रोडसाइड असिस्टेंस और इस साल 1 अप्रैल से पहले की गई बुकिंग के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री इंस्पेक्शन सर्विस सहित कई लाभ भी पेश किए हैं।

इंटीरियर और फीचर्स

फीचर्स के मामले में बीवाईडी सील 15-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ-साथ कनेक्टेड कार फीचर्स, डुअल वायरलेस चार्जिंग पोर्ट, डुअल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, फिक्स्ड पैनोरमिक सनरूफ और बहुत कुछ के साथ आता है। इसके अलावा, सील में 9 एयरबैग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, हेड-अप डिस्प्ले और लेवल-2 एडास जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।

स्पेसिफिकेशन और परफॉरमेंस

BYD ने Seal EV को तीन वेरिएंट में पेश किया है, जो सिंगल और डुअल-मोटर दोनों विकल्पों और बैटरी पैक के दो विकल्पों के साथ आते हैं। एंट्री-लेवल डायनेमिक और मिड-स्पेक प्रीमियम वेरिएंट रियर-व्हील ड्राइव तकनीक के साथ आते हैं, जबकि टॉप-एंड परफॉरमेंस वेरिएंट ऑल-व्हील ड्राइव तकनीक के साथ पेश किया जाता है।

डायनेमिक वेरिएंट 61.4 kWh की बैटरी से लैस है, जो एक बार चार्ज करने पर 510 किलोमीटर तक की रेंज प्रदान करती है। प्रीमियम और परफॉरमेंस दोनों वेरिएंट में बड़ा 82.56 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो एक बार चार्ज करने पर 650 किलोमीटर तक की रेंज प्रदान करता है। BYD बैटरी पर 8 साल या 1.60 लाख किलोमीटर की वारंटी और मोटर और मोटर कंट्रोलर के लिए 8 साल या 1.50 लाख किलोमीटर की वारंटी दे रही है।

परफॉरमेंस के मामले में BYD Seal डायनेमिक रेंज वेरिएंट 201 बीएचपी की पावर और 310 एनएम का पीक टॉर्क प्रदान करता है। प्रीमियम रेंज तीनों में से अधिक संतुलित संस्करण है, जो 308 बीएचपी की पावर और 360 एनएम का पीक टॉर्क उत्पन्न करता है। टॉप-एंड परफॉरमेंस वेरिएंट 522 बीएचपी की पावर और 670 एनएम का पीक टॉर्क उत्पन्न करता है। यह वेरिएंट 3.8 सेकंड में 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है।

बिना हेलमेट और सीट बेल्ट गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं, इस राज्य में 1 जून से होगी सख्ती

परिवहन आयुक्त-सह-सचिव राज यादव ने कहा कि दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने और सभी सड़क उपयोगकर्ताओं की भलाई की रक्षा के लिए यह आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि सीट बेल्ट पहनना हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) परिवहन वाहनों (टैक्सी और वाणिज्यिक) और गैर-परिवहन वाहनों (निजी और सरकारी) के लिए लागू होगा।

नई दिल्ली। बुधवार को जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, सिक्किम सरकार ने 1 जून से राज्य में वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट का उपयोग करना और मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है।

सिक्किम में सख्ती

परिवहन आयुक्त-सह-सचिव राज यादव ने कहा कि दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने और सभी सड़क उपयोगकर्ताओं की भलाई की रक्षा के लिए यह आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि जो कोई भी सुरक्षा बेल्ट पहने बिना मोटर वाहन चलाता है या सीट बेल्ट नहीं पहने यात्रियों को ले जाता है, वह केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 194 बी (1) के तहत दंडनीय होगा।

उन्होंने कहा कि सीट बेल्ट पहनना हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी), परिवहन वाहनों (टैक्सी और वाणिज्यिक) और गैर-परिवहन वाहनों (निजी और सरकारी) के लिए लागू होगा। इसी तरह, दोपहिया वाहन चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सीएमवी अधिनियम 1988 की धारा 129 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप सुरक्षात्मक हेडगियर पहनना होगा।

1 जून से लागू होगा नियम

परिवहन अधिकारी ने कहा कि जो कोई भी धारा 129 या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मोटरसाइकिल चलाता है या मोटरसाइकिल चलाने की अनुमति देता है, वह सीएमवी अधिनियम की धारा 194 सी के तहत दंडनीय होगा। परिवहन सचिव ने कहा कि यह आदेश 1 जून से लागू होगा।

ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नए नियमों से आपको कितना होगा फायदा, एक जून से होने जा रहा बदलाव; जानें पूरी डिटेल

नई दिल्ली। जून 2024 से भारत में ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियमों (नए ड्राइविंग लाइसेंस रूल्स) को लागू कर दिया जाएगा। जिसकी जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से दी गई है। नए नियमों के लागू होने के बाद किसे सबसे ज्यादा फायदा होगा। देश में कितनी तरह के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए जाते हैं। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

नए नियम होंगे लागू

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से घोषणा की गई है कि देशभर में 1 June 2024 से Driving License बनवाने के नियमों (New RTO Rules) को बदल दिया जाएगा। मंत्रालय की ओर से नए नियमों को आसान बनाया गया है, जिससे देशभर में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को काफी राहत मिलेगी।

कैसे मिलेगी राहत

नए नियमों के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस नहीं जाना होगा। इसकी जगह सरकार की ओर से उन संस्थानों को भी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जो ड्राइविंग सिखाते हैं। जिसके साथ ही आरटीओ में जाकर टेस्ट देने की जगह व्यक्ति ड्राइविंग स्कूल से ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले पाएगा।

कितने तरह के होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस

भारत में कई तरह के ड्राइविंग लाइसेंस को जारी किया जाता है। आमतौर पर देश में सबसे ज्यादा निजी कार और दो पहिया वाहन चलाने के लिए लाइसेंस को बनवाया जाता है। इसके अलावा कमर्शियल वाहन चलाने और दूसरे देशों में वाहन चलाने के लिए इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट को भी बनवाया जाता है।

एक लाख रुपये की डाउन पेमेंट के बाद घर लाएं मारुति वैगन आर का बेस वेरिएंट, जानें कितनी देनी होगी EMI

मारुति की ओर से हैचबैक सेगमेंट में Wagon R को ऑफर किया जाता है। कंपनी की इस कार को देश में बड़ी संख्या में लोग पसंद करते हैं। अगर आप भी इसे खरीदने का मन बना रहे हैं तो इसके बेस वेरिएंट LXI को एक लाख रुपये की डाउन पेमेंट के बाद कितने साल की EMI पर घर लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता की ओर से Wagon R को लंबे समय से भारतीय बाजार में ऑफर किया जाता है। हर महीने हजारों लोग इस कार को खरीदते हैं। ऐसे में आप भी इसे खरीदने का मन बना रहे हैं, तो हर महीने कितने रुपये देकर इसे घर लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

कितनी है कीमत

मारुति की ओर से Wagon R के बेस वेरिएंट LXI को 5.54 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जा रहा है। इसे दिल्ली में खरीदने पर कुल 6.06 लाख रुपये देने होंगे। इस कीमत में 5.54 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत के अलावा 23 हजार रुपये आरटीओ और 23351 रुपये का इंश्योरेंस और फास्टैग, स्मार्ट कार्ड सहित कुछ एक्सेसरीज भी शामिल है।

एक लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI

अगर इस गाड़ी के बेस वेरिएंट LXI को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में एक लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 5.06 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको 8.7 फीसदी ब्याज के साथ सात साल के लिए 5.06 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 8064 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

कितनी महंगी पड़ेगी कार

अगर आप 8.7 फीसदी की ब्याज दर के साथ सात साल के लिए 5.06 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 8064 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Maruti Wagon R के लिए करीब 1.71 लाख रुपये बतौर ब्याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्स शोरूम, ऑन रोड और ब्याज मिलाकर करीब 7.77 लाख रुपये देंगे।

भारत में किस तरह बनता है ड्राइविंग लाइसेंस, क्या है रिन्यू की स्टेप बाय स्टेप गाइड, जानें डिटेल

परिवहन विशेष न्यूज

देश में हर महीने बड़ी संख्या में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन बनवाए जाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जरूरी और सही जानकारी नहीं होती है जिससे लाइसेंस बनवाते समय परेशानी भी होती है। लाइसेंस बनवाने के लिए क्या Process होती है और बिना परेशानी इसे किस तरह Renew करवाया (Driving License Renewal Details) जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की ओर से देश भर में Driving License बनवाने की प्रक्रिया को लगातार आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जल्द ही नए नियमों को भी लागू कर दिया जाएगा। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ऑनलाइन तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाया और Renew करवाया जा सकता है।

Online है आवेदन प्रक्रिया

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने देशभर में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया हुआ है। सरकार की Parivahan वेबसाइट के जरिए किसी भी राज्य के व्यक्ति अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन बनवा या Renew करवा सकता है। लेकिन इसके लिए चरणबद्ध प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है।

कैसे करें आवेदन

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले Parivahan वेबसाइट के लिंक को ओपन करना होता है। इसके बाद पेज पर लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं में सबसे पहले ड्राइवर और लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग स्कूल, ऑनलाइन टेस्ट और अपाइंटमेंट के अलावा अन्य सेवाओं को उपयोग किया जा सकता है। यहां पर लाइसेंस बनवाने वाले बटन को प्रेस करने के बाद नया विंडो खुल जाता है। यह नया विंडो परिवहन के साथ सारथी सर्विस के साथ ओपन होता है, जिसमें देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम सामने आते हैं। इसके बाद कॉन्टेक्टलेस लाइसेंस सर्विस का पेज सामने आता है। इस पेज पर ही कुल 15 तरह की सेवाओं की सुविधा को लिया जा सकता है।

Contactless Service में करें चुनाव

कॉन्टेक्टलेस सर्विस में कुल 15 तरह की सेवाओं में से एक को चुनना होता है। जिसमें लर्नर लाइसेंस जारी करने, डुप्लीकेट डीएल जारी करने, पता बदलने, मोबाइल नंबर अपडेट करने, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, कमर्शियल लाइसेंस को रिन्यू और डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करने जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

लर्निंग और स्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन

इन सुविधाओं में से लर्निंग लाइसेंस के बटन को क्लिक करने के बाद नई विंडो खुल जाती है। जिसमें पूरी प्रक्रिया की जानकारी को दिया जाता है। इसमें बताया गया है कि सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन को पूरी तरह से भरा जाए, इसके बाद फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होता है। अगर ई-केवाईसी आधार से होती है तो सिर्फ सिग्नेचर को ही अपलोड करना पड़ता है। इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ता है। फिर फीस जमा करनी होती है। जिसके बाद फीस पेमेंट को वेरिफाई किया जाता है और रसीद का प्रिंट निकाला जा सकता है। इसके बाद लर्निंग लाइसेंस के लिए स्लॉट को बुक करना होता है।

ड्राइविंग लाइसेंस को ऐसे करवाएं रिन्यू

अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगले कुछ महीने में एक्सपायर होने वाला है, तो उसे रिन्यू करवाना जरूरी होता है। रिन्यू करवाने के लिए भी इसी वेबसाइट पर डीएल रिन्यूअल (Driving license renew in India) का विकल्प दिया जाता है। एक बार इस विकल्प पर क्लिक किया जाए तो नया पेज खुल जाता है। नए पेज में कुछ ज्यादा जानकारी को देना होता है। साथ ही फॉर्म को भी भरना होता है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स, फोटो सिग्नेचर और फीस देने के बाद टेस्ट का स्लॉट बुक किया जा सकता है और इसी तरह से रिन्यू (Licence Renewal Process) करवाया जा सकता है।

किन डॉक्यूमेंट्स की होती है जरूरत

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने और बनवाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट, फॉर्म1 और 1ए, स्कैन फोटो और सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट जैसे कागजातों के साथ ही पेमेंट करने के लिए यूपीआई, डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जरूरत होती है।

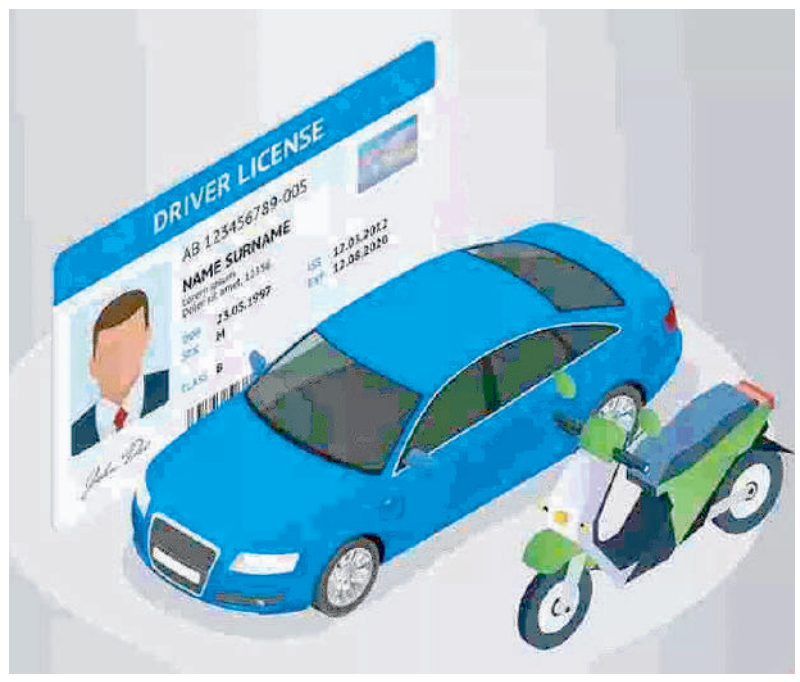

राजनीति और यौन शोषण

डा. वरिंद्र भाटिया

कर्नाटक के एक उच्च नेता के पोते से जुड़ा यौन शोषण का मुद्दा चर्चा में है। कटु सत्य है कि आज राजनीति और यौन शोषण एक-दूसरे के पूरक बन रहे हैं। अतीत में और आज तक दुनिया भर में राजनेताओं के सेक्स स्कैंडल में शामिल होने के अनगिनत मामले सामने आए हैं।

आज राजनीति में रसूख से कुछ भी हो सकता है। कद्दावर नेताओं ने अपनी जिंदगी में रसूख का इस्तेमाल कर महिलाओं के साथ ज्यादतियां भी की हैं। आज सेक्स शोषण के डर से महिलाएं राजनीति में आने से गुरेज करती हैं। क्या यह सच नहीं है कि बॉलीवुड के कास्टिंग काउच की तरह महिलाओं के लिए भी राजनीति में ऊंचा मुकाम हासिल करने का रास्ता पॉलिटिकल बेडरूम से होकर निकलता है। महिलाएं, हमेशा की तरह, कामुक राजनेताओं के लिए आसान शिकार हैं और इतिहास में ऐसे कई मामले देखे गए हैं जहां इन लोगों के तथाकथित लोक सेवकों ने अपने मतदाताओं की माताओं, बेटियों और बहनों के प्रति अनादर दिखाया है'

कर्नाटक के एक उच्च नेता के पोते से जुड़ा यौन शोषण का मुद्दा चर्चा में है। कटु सत्य है कि आज राजनीति और यौन शोषण एक-दूसरे के पूरक बन रहे हैं। अतीत में और आज तक दुनिया भर में राजनेताओं के सेक्स स्कैंडल में शामिल होने के अनगिनत मामले सामने आए हैं। इस बिन्दु पर अपना देश भी अपवाद नहीं है। सत्ता की खुमारी के साथ अपनी वासनाओं को तृप्त करने की इच्छा को पूरी करने वाली कुछ खास शख्सियतों की प्रेमलीला हमेशा से ही दिल लुभाती रही है। कुछ समय पहले पाकिस्तान की फिजाओं में हिना और बिलावल के अफेयर के किस्से काफी मसाले के साथ उड़ रहे थे। कुछ अरसा पहले बांग्लादेश के एक वीकली टेबलॉयड की खबर में कहा गया था कि हिना और बिलावल का इश्क काफी हद तक परवान चढ़ चुका था और दोनों शादी करने का मन बना चुके थे। हिना तो बिलावल के लिए अपनी शादीशुदा जिंदगी को खत्म करने का मन बना चुकी थी। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के भी किस्से कम चटपटे नहीं थे। क्लिंटन के बारे में तो यह कहा जाता है कि वे एक साथ कई लड़कियों से सेक्स संबंध बनाते थे। राष्ट्रपति निवास में इंटर्न मोनिका लेविंस्की के साथ उनके अंतरंग संबंधों के किस्से तो काफी चर्चित हैं। लीबियाई तानाशाह नेता मुअम्मर अल गद्दाफी के नौकर की मानें तो गद्दाफी भी सेक्स के आदी थे। साल 2008 में गद्दाफी ने ब्रिटिश ट्रेड एंबेसेडर प्रिंस एंड्रयू के साथ मुलाकात से कुछ घटों पहले चार महिलाओं के साथ संबंध बनाए थे। फैसल के मुताबिक ये महिलाएं कोई और नहीं बल्कि गद्दाफी की बॉडीगार्ड थीं।

मीडिया रिपोर्ट बताती है कि इटली के एक प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी ने मिलान स्थित अपने विला में मोरक्को की एक टीनएजर के साथ 13 बार पैसे देकर सेक्स संबंध बनाए। खबर तो यहां तक है कि बर्लुस्कोनी इस तरह का अय्याश रहा कि उसके सहयोगी लड़कियों का इंतजाम करते थे। न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर इलियट स्पाइजर का नाम तो सेक्स स्कैंडल में इस तरह उछला कि उन्हें अपने पद से हाथ धोना पड़ा। पेशे से गायिका अलेक्जेंड्रा डुप्रे से उनका शारीरिक संबंध था। डुप्रे को एक घंटे के लिए वो एक हजार डॉलर देते थे। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी की कहानियां तो और भी मजेदार हैं। कई लड़कियों के साथ सेक्स और अपनी न्यूड तस्वीरों को जारी करने में हैरी भी कम नहीं। भारतीय राजनीति में भी ऐसे कई सेक्स स्कैंडल सामने आए हैं जिन्हें जानकर पूरा देश हैरान हो जाता है। यह पहला मामला नहीं है, जब किसी सेक्स स्कैंडल का असर राजनीति में पड़ा है। प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार 1978 में मेनका गांधी की पत्रिका ने एक ऐसे ही मामले का खुलासा कर बाबू जगजीवन राम जी की राजनीति खत्म कर दी थी। बेटे के सेक्स स्कैंडल ने जगजीवन राम जी का सपना तोड़ दिया। मीडिया पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1978 में सूर्या नाम की पत्रिका ने बाबू जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम के सेक्स स्कैंडल का खुलासा किया। इस पत्रिका की संपादक एक वर्तमान नेत्री थीं। पत्रिका में सुरेश की कई अश्लील तस्वीरें भी छापी गई थीं। इन तस्वीरों को पत्रिका में छाप दिया गया। इन तस्वीरों में जो महिला सुरेश के साथ थी वह उनकी कथित गर्लफ्रेंड थी और अश्लील तस्वीरें सामने आने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली थी। हालांकि, इन सबके बीच जगजीवन राम प्रधानमंत्री पद की रेस से पूरी तरह बाहर हो गए। इसी कड़ी में 2009 में दिवंगत एनडी तिवारी का स्कैंडल बहुत चर्चित था।

जिस समय यह सेक्स स्कैंडल सामने आया था उस वक्त एनडी तिवारी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के पद पर थे। एक स्टिंग ऑपरेशन में राज भवन के अंदर आधिकारिक निवास में उनको तीन महिलाओं के साथ बिस्तर पर दिखाया गया था। इस घटना से पूरा देश सकते में आ गया था। किसी को इस टेप पर विश्वास ही नहीं हुआ था। इस टेप के सामने आने के बाद एनडी तिवारी ने माफी मांगते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 2011 में महिपाल मदेरणा-भंवरी देवी का स्कैंडल भी सुर्खियों का हिस्सा बना था। पेशे से नर्स भंवरी देवी और राजस्थान सरकार में मंत्री महिपाल मदेरणा का सेक्स स्कैंडल सामने आया था जिस पर काफी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। भंवरी देवी एक सीडी की धमकी देकर विधायक मलखान सिंह और मदेरणा से करोड़ों रुपए मांग रही थी। उस सीडी में मदेरणा और अन्य लोग भंवरी देवी के साथ आपत्तिजनक हालत में थे। यह मामला उस समय सामने आया था, जब भंवरी देवी के पति ने आरोप लगाया कि मदेरणा ने उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया है। इस आरोप पर जांच हुई थी तो यह सेक्स स्कैंडल सामने आया था। इसके बाद राजस्थान सरकार ने भंवरी देवी के मर्डर केस में महिपाल को अरेस्ट कर लिया था। इसी कड़ी में 1992 में अजमेर के सोफिया स्कूल से जुड़ा एक सेक्स स्कैंडल सामने आया था, जिसमें 17-20 साल की 100 से ज्यादा लड़कियों का यौन शोषण होने की बात सामने आई थी। मामले के मुख्य आरोपी ने पहले एक लडक़ी को फंसाया था। उसके साथ अश्लील तस्वीरें खींची और ब्लैकमेल कर फॉर्म हाउस में उसका यौन शोषण करता रहा। उस लडक़ी पर दबाव बनाया और दूसरी लड़कियों को भी फॉर्म लाने के लिए कहा। इसके बाद एक-एक कर 100 से ज्यादा लड़कियां इसकी शिकार हुईं। हमारे आसपास कद्दावर लोग राजनीतिक शक्ति को अंतिम लाइसेंस मानते हैं जो उन्हें कुछ भी जीत कर दिला सकती है और जो उन्हें सब कुछ से बच निकलने में सक्षम भी बनाती है। हम यह समझें कि लव, सेक्स और धोखा सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही होता है, तो हम गलत हैं।

राजनीतिक दुनिया इसकी मौसी जैसी बन गयी है। आज राजनीति में रसूख से कुछ भी हो सकता है। कद्दावर नेताओं ने अपनी जिंदगी में रसूख का इस्तेमाल कर महिलाओं के साथ ज्यादतियां भी की हैं। आज सेक्स शोषण के डर से महिलाएं राजनीति में आने से गुरेज करती हैं। क्या यह सच नहीं है कि बॉलीवुड के कास्टिंग काउच की तरह महिलाओं के लिए भी राजनीति में ऊंचा मुकाम हासिल करने का रास्ता पॉलिटिकल बेडरूम से होकर निकलता है। महिलाएं, हमेशा की तरह, कामुक राजनेताओं के लिए आसान शिकार हैं और इतिहास में ऐसे कई मामले देखे गए हैं जहां इन लोगों के तथाकथित लोक सेवकों ने अपने मतदाताओं की माताओं, बेटियों और बहनों के प्रति अनादर दिखाया है। अंत में यह कहना उचित होगा कि नैतिकता और राजनीति एक-दूसरे के विरोधाभासी हैं और सेक्स शोषण राजनीति का टॉनिक बन गया है। कुछ हद तक इसके लिए कुछ महिलाएं भी कसूरवार हैं, जो राजनीतिक हवाखोरी के लिए अस्मत का सौदा करती हैं। इसे रोकना होगा क्योंकि राजनीति में नैतिकता उतनी ही महत्त्वपूर्ण है जितनी कि जीवन के किसी अन्य पहलू में इसकी आवश्यकता होती है।

संपादकीय

गर्मी का एहसास

कभी हिमाचल ग्रीष्म ऋतु के काबिल और मुकाबिल था, लेकिन अब वो फिजाएं शर्मिंदा हैं। वर्तमान दौर की गर्मी ने हिमाचल के कई हिल स्टेशन तक को पसीना-पसीना कर दिया है, तो यह स्थिति हमारी योजनाओं-परियोजनाओं की चुगली कर रही है। कंक्रीट के घनत्व में होता विकास और जीवन शैली की नव अदाओं में फंसा उपभोक्तावाद, हमारे जुर्म की स्वीकारोक्ति है। हिमाचल को अगर मौसम विभाग के नक्शे पर पढ़ा जाए, तो पर्यटन का यह सीजन एक अलग तरह की चेतावनी है। बेशक चढ़ती गर्मी ने पर्यटन की खुमारी बढ़ा दी है, लेकिन इसके भीतर की बीमारी नहीं समझी तो मुफ्त में बदनाम हो जाएंगे। हम अटल टनल के दोनों छोरों पर नाच कर किसे डरा रहे। एक हफ्ते में करीब तीन लाख पर्यटकों का जमावड़ा हमारी संगत का नशा है या इसकी धमक उन ग्लेशियरों से मुखातिब होगी जो पहले ही ऊना के चढ़ते पारे से खुद को बचाने के लिए हाय तौबा मचा रहे हैं। एक सप्ताह में 55 हजार के करीब वाहनों का द्वार बनी अटल टनल की हैरानी समझी जानी चाहिए। आखिर यह पर्यटन है किस कीमत पर। पूरा साल एक तरफ और गर्मियों का पर्यटन दूसरी तरफ। अगर हम अस्सी प्रतिशत पर्यटकों के लिए अपनी गर्मियों को हाजिर कर रहे हैं, तो यह सीजन सुविधाओं का नहीं, दुविधाओं का है।

ट्रैफिक जाम की गर्मी में पर्यटक सीजन की नकारात्मक तस्वीर का एक पहलू यह कि शिमला, मनाली, मकलोडगंज, मंडी सहित अनेक डेस्टिनेशन परिवहन की त्रासदी बन चुके हैं। पर्यटन का एहसास अगर प्रदेश की नेमत नहीं बन रहा तो एक दिन कारवां उजड़ जाएगा, इसलिए पर्यटन सीजन को पूरे साल में बांटना होगा, खास तौर पर धार्मिक और संत समागमों को ग्रीष्मकालीन महीनों में अनुमति नहीं देनी होगी। ग्रीष्मकाल में हिमाचल की अपनी जरूरतों के मुताबिक बिजली, पानी और सिंचाई की आपूर्ति केवल कुछ गुंजाइश छोड़ती है। ऐसे में पांच करोड़ पर्यटकों के लक्ष्य में अस्सी फीसदी हिस्सा कल अगर गर्मियों में पहुंच गया, तो सारी व्यवस्था ठप हो जाएगी। भले ही जलवायु परिवर्तन के कारणों से दबा अलनीनो कमजोर होकर उत्तर भारत के तापमान को बढ़ा रहा है, लेकिन इसकी बदलती भूमिका में पहाड़ का दर्द बढ़ रहा है। हिमाचल जैसे राज्य के लिए हर ऋतु का नियमित व्यवहार अपेक्षित है, लेकिन आगे सरक रहे मौसम के व्यवहार ने अतिवादी रुख अपनाना शुरू किया है। मई के आरंभ तक सर्दी में दिन गिन रहे हिमाचल को अगर अब भयंकर गर्मी में उबलना पड़ रहा है, तो इसके साथ जुड़ी हिदायतों में स्थानीय निकायों की योजनाएं-परियोजनाएं नत्थी हैं। कृषि-बागबानी विभाग को नए सिरे से घुंघरू पहनने पड़े हैं, तो बरसाती इंतजामों की जद में एक नया चेतावनी सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा।

हद यह कि गर्मियों में लगभग सूखने के कगार पर खड्डें और नाले आगे चलकर बरसात में खूनी मंजर से भर जाते हैं। ऐसे में जल प्रबंधन की नाव को एक ओर सुरक्षा का छोर चाहिए, तो दूसरी ओर आपूर्ति के लिए जलधारा की उत्पत्ति चाहिए। विडंबना यह है कि जल शक्ति विभाग सीधे जल के उद्गम को निचोड़ते-निचोड़ते गर्मियों में लाचार और फटेहाल हो जाता है, फिर भी कोई सबक नहीं सीखता। जो जल प्रपात हमारे पर्यावरण व पर्यटन की आभा को संरक्षित कर सकते हैं, उनके हलक से भी अनावश्यक पानी खींच कर विभाग ने खतरे पैदा कर दिए हैं। धर्मशाला का भागसू जल प्रपात इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहां सेना की छावनी ने इसके अस्तित्व को ही सुखा दिया है। हिमाचल कल तक मौसम की उलझन में सिर्फ बर्फबारी पर ही सचेत होता था, जबकि अब गर्मी और बरसात भी इसका चीरहरण कर रहे हैं। चढ़ते पारे की सुर्खियों में हिदायतों को जितना जल्दी पढ़ेंगे, उतना ही सही होगा।

राय

शहरी उदासीनता का चुनाव

आम चुनाव, 2024 के 5वें चरण के मतदान के साथ ही 428 लोकसभा सीटों पर चुनाव सम्पन्न हो गया। गुजरात में एक निर्वाचन निर्विरोध हुआ था। शेष 114 सीटों के लिए दो चरण मतदान अभी होने हैं। उसके बाद ही जनादेश का विश्लेषण किया जा सकता है। दरअसल इस बार चुनाव की बुनियादी चिंता यह रही कि शहरी मतदाता अपेक्षाकृत उदासीन रहा। उसने मतदान के प्रति दायित्व और मताधिकार के महत्व को कमतर आंका, नतीजतन मतदान के शुरुआती आंकड़े निराश करते रहे। हालांकि अपडेट मतदान पहले चरण में 66.14 फीसदी, दूसरे में 66.71 फीसदी, तीसरे में 65.68 फीसदी और चौथे चरण में 69.16 फीसदी तय किया गया है। विपक्ष ने इन बढ़े आंकड़ों पर भी सवाल उठाया कि चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है, लेकिन मतदान को अद्यतन करने में कुछ दिन लगे, इस पर कोई भी सर्वोच्च अदालत तक नहीं गया। चुनाव आयोग ने भी स्पष्टीकरण दिया कि इतने बड़े देश के, कोने-कोने से, मतदान के आंकड़ों को जुटाने और संयोजित करने में वक्त लगना सहज प्रक्रिया है। बहरहाल मतदान के अब जो आंकड़े सामने आए हैं, वे सम्मानजनक हैं, अलबत्ता 2019 के चुनाव की तुलना में अब भी कम हैं। चुनाव के 5वें चरण में भी, 20 मई रात्रि 11.45 बजे तक, आठ राज्यों और संघशासित क्षेत्रों की 49 सीटों पर 60.3 फीसदी मतदान दर्ज किया गया। यह 2019 के 5वें चरण के 62.5 फीसदी मतदान से कुछ कम रहा है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि शुक्रवार, 24 मई तक मतदान का अंतिम आंकड़ा दर्ज किया जा सकता है, लिहाजा मतदान के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है। बहरहाल दो जगह पर मतदान बड़ा उत्साहवर्धक रहा है और दोनों ही कश्मीर के हिस्से रहे हैं।

लद्दाख आज संघशासित क्षेत्र है, जो जम्मू-कश्मीर राज्य का ही हिस्सा था, वहां करीब 70 फीसदी मतदान किया गया। दूसरा क्षेत्र बारामूला है, जो नियंत्रण-रेखा के करीब है और आतंकियों की पनाहगाह रहा है। इस संसदीय सीट में सोपोर भी सम्मिलित है, जो पत्थरबाजी के गढ़ के तौर पर कुख्यात था। वहां हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं का भी खूब प्रभाव था, लिहाजा चुनावों के बहिष्कार होते रहते थे। इस बार सोपोर और पहलगाम आदि इलाकों में मतदाताओं की लंबी-लंबी कतारें देखी गईं, तो लगा कि 'जन्नत का जम्हूरियत' यही है। बारामूला सीट पर 1984 के बाद पहली बार 50 फीसदी से अधिक मतदान हुआ है। वहां 57.4 फीसदी मतदान किया गया है, जो 40 साल के बाद एक कीर्तिमान दर्ज किया गया है। यकीनन भारत और कश्मीर बदल रहे हैं, लेकिन सवाल है कि महाराष्ट्र में सबसे कम 54.3 फीसदी मतदान ही क्यों हुआ? दूसरा सबसे कम मतदान 54.9 फीसदी बिहार में क्यों किया गया? सबसे बड़े राज्य उप्र में भी मतदान 60 फीसदी से कम रहा, हालांकि राहुल गांधी की सीट रायबरेली और पूर्व संसदीय क्षेत्र अमेठी में मतदान 2019 की तुलना में अधिक हुआ है। सबसे अधिक मतदान 74.7 फीसदी पश्चिम बंगाल में दर्ज किया गया। वहां अक्सर मतदान लबालब होता है, फिर भी 2019 की तुलना में कम रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बॉलीवुड की दुनिया है, अधिकतर अरबपति वहां रहते हैं, माफिया-डॉन भी मुंबई से जुड़े रहे हैं, बेहद मेहनतकश लोगों का महानगर है, लेकिन मतदान 47.7 फीसदी (मुंबई साउथ) और 55.2 फीसदी (मुंबई उत्तर) के बीच रहा है।

मतदान में युवाओं की अत्यावश्यक भूमिका

सिर्फ युवाओं तक सीमित न रहते हुए इसके जरिए स्थानीय राजनीति में प्रवासियों के मुद्दों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। संयुक्त कार्यक्रम भी चले...

भारत को अपने मूल लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मजबूत बनाने के लिए अपनी युवा शक्ति का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए और राजनीति व लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 18-19 साल के महज 790000 युवा मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं जबकि राज्य में इस आयु वर्ग के युवाओं की संख्या 4209000 है। राज्य की कुल जनसंख्या में 18-19 साल के युवाओं की संख्या 4.5 प्रतिशत है, लेकिन इस आयु वर्ग में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या राज्य की आबादी का महज 0.6 प्रतिशत है। राज्य भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नियमित रूप से मतदाता पंजीकरण अभियान चलाए जाने के बावजूद, 18-19 आयु वर्ग में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में मामूली सुधार हुआ है। जहां नवंबर 2022 में ऐसे मतदाताओं की संख्या कुल आबादी का 0.3 प्रतिशत थी, वहीं अप्रैल 2023 के लिए यह आंकड़ा 0.6 प्रतिशत था। चूंकि मतदाता पंजीकरण एक जीवंत, समावेशी और मजबूत सहभागिता वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहली सीढ़ी है, ऐसे में मतदान के प्रति युवाओं की उदासीनता के कारणों को दूर करना जरूरी है। इन आंकड़ों से देश भर में शहरी मतदाताओं की उदासीनता का पता चलता है, जहां राष्ट्र और राज्य स्तर के चुनावों की तुलना में स्थानीय चुनावों में बेहद कम मतदान होता है। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि देश के कई शहरी युवा अपने मताधिकार के प्रयोग से दूर रहे हैं, और इस बात को लेकर राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में भी चिंता जताई गई है। नीति में राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर देने के अलावा यह भी कहा गया है कि राजनीति और प्रशासन में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए बेहद कम समन्वित प्रयास किए गए हैं।

भारत की राजनीति को 'युवा देश, बूढ़े नेता' के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारतीय राजनीति में अपनी धाक जमाने वाले ज्यादातर युवा नेता बड़े राजनीतिक परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, जो सामाजिक-राजनीतिक रूप से बेहद प्रभावशाली हैं। हालांकि मुख्यधारा की लगभग हर राजनीतिक पार्टी का अपना एक स्टूडेंट विंग है और ये सभी पार्टियां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनावों में जोर शोर से भाग लेती हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यवस्थित तंत्र मौजूद नहीं है जो छात्र नेताओं को विधायी राजनीति में आगे बढने में मदद कर सके और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान कर सके। उदाहरण के लिए, 17वीं लोकसभा (2019-2024) में 40 वर्ष के कम उम्र सांसदों की संख्या महज 12 प्रतिशत है, वहीं स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा में 26 प्रतिशत सांसदों की उम्र 40 वर्ष से कम थी। खासकर (हर बड़े) चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणापत्रों में युवाओं के लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू करने की बात करती हैं, जिनका अखबारों और सोशल मीडिया के जरिए भारी प्रचार किया जाता है। राजनीतिक संपर्क अभियानों में बड़े पैमाने पर युवाओं को शामिल किया जाता है और राजनीतिक पार्टियां शक्ति प्रदर्शन के लिए चुनावी रैलियों में युवाओं की भागीदारी को प्रचारित करती हैं। हालांकि, चुनाव के बाद युवाओं के मुद्दों (शिक्षा और रोजगार) को तरजीह नहीं दी जाती, जो चुनावी राजनीति में युवाओं की कमजोर स्थिति को बताता है क्योंकि उनमें अपनी मांगों को मजबूती से रखने की क्षमता नहीं है। यहां तक कि छात्र नेता जब विधायी चुनावों में शामिल होते हैं, तो उनके पास राजनीतिक सौदेबाजी की ताकत बेहद सीमित होती है।

इस तरह से देखें तो यही लगता है कि युवाओं की मतदाता भागीदारी अगर कम है तो यह एक विचित्र घटना न होकर एक अपेक्षित परिणाम मात्र है। भारत की राजनीतिक पार्टियों और नीति निर्माताओं को ऐसे रास्ते तलाशने होंगे जिनके जरिए युवाओं तक पहुंच बनाई जा सके और उन्हें देश की विकास यात्रा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। प्रतिनिधित्व के सवाल के अलावा, युवाओं की भागीदारी बढने से उनसे जुड़े मुद्दों को भी ज्यादा अहमियत मिलेगी। शिक्षा और रोजगार से जुड़ी पारंपरिक चुनौतियों के अलावा शासन तंत्र को युवाओं को प्रभावित करने वाले दूसरे अन्य मुद्दों का भी समाधान करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जापान और चीन जैसे विकसित देशों में बच्चे न पैदा करने के पीछे वित्तीय दबाव एवं पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएं जिम्मेदार हैं, ऐसे रुझान भारत में भी देखे जा रहे हैं, जहां ऐसी महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है जो बच्चे न पैदा करने का विकल्प चुन रही हैं और बहुत कम युवा शादी का विकल्प चुन रहे हैं। यहां मुद्दा यह नहीं है कि नतीजे क्या हैं, बल्कि उन्हें प्रभावित करने वाले कारक और उनके प्रबंधन के तौर-तरीके समस्या की मुख्य जड़ हैं, जबकि संबंधित सरकारी रिपोर्टें सामाजिक मानसिकता में बदलाव का अध्ययन करती हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि भारत युवाओं से जुड़ी नई समस्याओं का सामना कैसे कर रहा है, जिसके लिए शहरी दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। चुनावों में युवा मतदाताओं की भागीदारी किस तरह से मीडिया जगत, लैंगिक प्रथाओं एवं वयस्कों और युवाओं के बीच साझेदारी से प्रभावित होती है, इस मुद्दे पर टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च ऑन सिविक लर्निंग एंड एंगेजमेंट के तहत विशेष अध्ययन किया गया है। चुनावों में शहरी युवाओं की कम भागीदारी को देखते हुए ऐसी पहलों को लागू किए जाने की जरूरत है जहां समस्या के अनुरूप रणनीतियां तैयार की जाएं।

शिक्षा, रोजगार, विवाह और काम के लिए भारतीय युवाओं को देश के भीतर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, यानी इन कारणों के चलते युवाओं के आंतरिक प्रवासन को बढ़ावा मिला है। भारत के चुनाव आयोग को ऐसे रास्ते ढूंढने होंगे जिससे गांवों और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले इन प्रवासी युवाओं को घर वापस लौटे बगैर अपने मूल निवास स्थान से मतदान करने का मौका मिले। सरकार को इस उद्देश्य के लिए अपने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की सफलताओं का लाभ उठाना चाहिए। सिर्फ युवाओं तक सीमित न रहते हुए इसके जरिए स्थानीय राजनीति में प्रवासियों के मुद्दों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। डिजिटल हस्तक्षेपों के अलावा ऐसे मामलों में विभागों के आपसी समन्वय से संयुक्त कार्यक्रम चलना चाहिए।

किस्सा घडिय़ाल की बिन आंसुई आंखों का

घडिय़ाल की आंखें बिन आंसुओं के? मुझे लगा, उसकी आंखों में कहीं कोई दिक्कत न हो गई हो। असल में क्या है कि जिनकी जो फितरत होती है, उनमें वह न दिखे तो आपकी तो आप जानो, पर मेरे जैसे बंदे परेशान जरूर हो जाते हैं। 'और घडिय़ाल भाई! तुम्हारी आंखें कैसी हैं? तुममें और तो सब कुछ पुराना ही नजर आ रहा है, पर तुम्हारी आंखों में आंसू नजर नहीं आ रहे।

स्वास्थ्य लाभ के बहाने मार्निंग टॉक करता आज भी निकला था कि रास्ते में घडियाल मिल गया। जनाब भी मार्निंग वॉक करने के बहाने मार्निंग टॉक करने निकले थे। यही तो वक्त होता है जब चंद लोग सडक़ में चलते हुए मिल जाते हैं, उनसे दुआ सलाम हो जाती है। वर्ना शेष सारा दिन तो खुद ही खुद की सलामती की दुआएं करते रहो। घडियाल मेरे हालचाल पूछता मेरे साथ साथ चलने लगा तो मैंने पता नहीं क्यों उसकी आंखों में झांका। वैसे मैं बहुधा औरों की जेबों में झांका करता हूं। उसकी आंखों में झांका तो लगाए यार! इसकी आंखों से तो आंसू गायब हैं तो अचंभा हुआ। घडियाल की आंखें बिन आंसुओं के? मुझे लगा, उसकी आंखों में कहीं कोई दिक्कत न हो गई हो। असल में क्या है कि जिनकी जो फितरत होती है, उनमें वह न दिखे तो आपकी तो आप जानो, पर मेरे जैसे बंदे परेशान जरूर हो जाते हैं। 'और घडियाल भाई! तुम्हारी आंखें कैसी हैं? तुममें और तो सब कुछ पुराना ही नजर आ रहा है, पर तुम्हारी आंखों में आंसू नजर नहीं आ रहे। आखिर क्या हो गया तुम्हारी आंखों को? मेरी समझ से इससे पहले कि आंखों का कुछ का कुछ हो जाए किसी हड्डियों के अच्छे से डॉक्टर को अपनी आंखें बता लो।' 'ऐसा कुछ नहीं भाई साहब जैसा आप समझ रहे हैं। पर इसके लिए दिल से थैंक यू कि आपने कम से कम मेरी आंखों में तो झांका। मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। असल में क्या है न पिछले हफ्ते एक नेताजी मेरे घर आए। दोनों हाथ जोड़े अपनी टोपी मेरे चरणों में रख बोले, 'रे घडियाल भाई! अब मेरी जीत तुम्हारे हाथ।

तुम तो जानते ही हो कि चुनाव के दिन हैं। चुनाव के दिनों में बात बात पर जो नेता जनता के आगे जितना रोता है वह उतना ही कुर्सी पर अगले पांच सालों के लिए कुंभकरण हो सोता है। चुनाव प्रचार के दौरान जनता के आगे बात बात पर रोते रोते मेरे आंसू खत्म हो गए हैं। अब मैं तुम्हारी शरण में आया हूं।' 'तो कहिए मैं आपके किस तरह काम आ सकता हूं?' मैंने द्रवित हो नेताजी से पूछा तो वे बोले, 'कुछ दिनों के लिए अपने आंसू उधार दे दो तो चुनाव खत्म होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे आंसू सादर सूद सहित लौटा दूंगा। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं।' 'पर नेता पर विश्वास कौन करे? कल को कहीं ऐसा न हो कि तुम मुझसे मेरे आंसू उधार लेकर लौटाने से मुकर जाओ और मैं सदियों से चली आ रही कहावत से हाथ धो बैठूं', मैंने दो टूक कहा तो वे बोले, 'मैं जनता से धोखा कर सकता हूं पर अपने मौसेरे भाई से नहीं। मैं अपने खुदा से धोखा कर सकता हूं, पर अपने मौसेरे भाई से नहीं। मुझ पर विश्वास नहीं तो लो, मैं गारंटी देता हूं। ये ऐसे वैसे की गारंटी नहीं, नेशनल नेता की गारंटी है', और मैंने उन्हें अपनी एक आंख के आंसू उधार दे दिए। लेकिन जैसे ही दूसरे दल के नेता को इस बात का पता चला कि मैंने उनको अपने आंसू उधार दिए हैं तो वे भी मेरे घर आ धमके। आते ही बोले, 'हद है घडियाल भाई! मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो।' 'मतलब! मैं कुछ समझा नहीं भाई साहब!' सच कहूं तो मैं कुछ समझा भी नहीं था। 'मेरे होते हुए भी तुमने मेरे विरोधी को अपने आंसू उधार दे दिए जनता को बहलाने के लिए? कल टीवी पर उनके आंसुओं को देख मैं एकदम समझ गया था कि बंदे के ये आंसू अपने नहीं। कहीं से पक्का मार कर लाया है। जब उनकी पार्टी में अपने खुफियाओं से संपर्क साधा तो उन्होंने बताया कि वे तुमसे आंसू उधार ले गए हैं। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। तुम कहीं से भी मैनेज करो, बस, मुझे तुम्हारे आंसू चाहिए चुनाव तक। चुनाव संपन्न होते ही मैं तुम्हारे आंसू तुम्हें सादर एक सौ प्रतिशत पर डे सूद समेत लौटा दूंगा।

अगर तुम्हारे आंसुओं से जनता का दिल जीत गया तो तुम्हें गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हें किसी न किसी बोर्ड का चेयरमैन पक्का बनाऊंगा। और मैंने जनहित में अपनी दूसरी आंख के आंसू उन्हें दे दिए। इसे केवल मेरा चुनावी दिनों में नेताओं को दिया आंसूदान समझिए। इसलिए मेरी ही क्या, मेरी तमाम बिरादरी की आंखें इन दिनों बिन आंसुओं के हैं। बंधु! हमारे आंसुओं से किसी का भला हो जाए तो हम घडियाली आंसुओं को बदनाम घडियालों को और चाहिए भी क्या!' घडियाल ने अपनी आंखों के सूखे आंसुओं का किस्सा सुनाया तो मेरी आंखों में सच्ची के आंसू आ गए। तब उसने मेरी आंखों में आए आंसुओं में से दो बूंद आंसू लेकर मेरा धन्यवाद करते अपनी आंखों में डाल लिए।

गिर गए सोने के दाम, चांदी ने फिर लगाई छलांग; गोल्ड 74,600 रुपये प्रति 10 ग्राम

राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को सोने की कीमत 50 रुपये गिरकर 74600 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। पिछले सत्र में पीली धातु 74650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। हालांकि चांदी की कीमत 600 रुपये उछलकर 95100 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। पिछले सत्र में यह 94500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। यहां चेक करें कीमत.....

नई दिल्ली। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार विदेशी बाजारों में कीमती धातु की कीमतों में गिरावट के बीच राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को सोने की कीमत 50 रुपये गिरकर 74,600 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। पिछले सत्र में पीली धातु 74,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी।

हालांकि, चांदी की कीमत 600 रुपये उछलकर 95,100 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। पिछले सत्र में यह 94,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था।

वैश्विक बाजारों में सोने की कीमत

वैश्विक बाजारों में कॉमेक्स पर सोना हाजिर 2,417 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, पिछले बंद से 3 अमेरिकी डॉलर नीचे था। बुधवार को सोना और गिर गया क्योंकि निवेशकों ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के हालिया बयानों का मूल्यांकन किया, जिसमें ब्याज दर में कटौती के समय को कम कर दिया गया था।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज में कमोडिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा कि व्यापारी अब बुधवार को जारी होने वाली यूएस फेड की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) की बैठक के मिनटों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, क्योंकि वे अमेरिकी केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति प्रक्षेपवक्र पर नए दृष्टिकोण पेश कर सकते हैं।

हालांकि, चांदी बढ़त के साथ 31.75 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। पिछले सत्र में यह 31.60 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ था।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज

इस बीच, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर वायदा कारोबार में सोना 171 रुपये की गिरावट के साथ 73,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। सबसे अधिक कारोबार वाला जून अनुबंध 1630 बजे इंट्रा-डे के निचले स्तर

73,742 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।

इसके अलावा, जुलाई डिलीवरी के लिए चांदी अनुबंध भी 256 रुपये या 0.27 प्रतिशत की गिरावट के साथ 94,469 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था।

रुकल रात से सोने में मामूली मुनाफावसूली देखी गई है क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर दुर्घटना से शुरुआती भू-राजनीतिक तनाव कम हो गया है। बाजार का ध्यान अब ब्याज दर में कटौती की भविष्यवाणी पर केंद्रित हो गया है, जो सितंबर में होने की उम्मीद है।

एलकेपी सिक्योरिटीज में कमोडिटी और करेंसी के वीपी रिसर्च एनालिस्ट जतीन त्रिवेदी ने कहा कि भारत में सोना फिलहाल 74,500 रुपये पर प्रमुख प्रतिरोध के साथ कम भाव पर है। मामूली मुनाफावसूली जारी रह सकती है, जिससे संभावित रूप से कीमतें 73,000 रुपये तक नीचे आ सकती हैं।

शेयरखान बाय बीएनपी पारिबा के एसोसिएट वीपी, फंडामेंटल करेंसीज एंड कमोडिटीज, प्रवीण सिंह के अनुसार, अमेरिका के महत्वपूर्ण मैक्रो डेटा, जिसमें यूएस की मौजूदा घरेलू बिक्री (अप्रैल) और यूके के सीपीआई (अप्रैल) डेटा भी शामिल होंगे और फोकस में होंगे।

गोल्ड की कीमतों में आई तेजी के बाद भर रही है व्यापारियों की झोली, FY25 में 17-19 फीसदी बढ़ेगा रेवेन्यू: CRISIL

देश में लगातार सोने की कीमतों में तेजी आ रही है। सोने की कीमतों में आई तेजी से सोने के कारोबारियों को लाभ होगा। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल (CRISIL) ने रिपोर्ट में कहा कि सोने की कीमतों में आई तेजी से इस वित्त वर्ष में व्यापारियों का रेवेन्यू 17 से 19 फीसदी तक बढ़ सकता है। इस आर्टिकल में जानते हैं कि सोने की कीमतों में क्यों तेजी आ रही है।

नई दिल्ली। देश में सोने की कीमतों में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। माना जा रहा है कि इस साल अंत में सोना 1 लाख रुपये के पार पहुंच जाएगा। सोने की कीमतों में आई तेजी से ज्वेलर्स को लाभ हो रहा है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल (CRISIL) ने इसको लेकर रिपोर्ट पेश किया है।

क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार सोने की कीमतों में तेजी के बाद भी इसकी बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मजबूत बिक्री होने से खुदरा विक्रेता को मुनाफा होगा। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में ज्वेलर्स के रेवेन्यू में 17 से 19 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि सोने की कीमतों में तेजी आने के बावजूद इसकी डिमांड स्थिर रहेगी। निवेश के लिए सुरक्षित निवेश माना जाने वाला सोना काफी समय से मांग में है और इसकी कीमतें समय-समय पर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच रही हैं।

सोने की कीमतों में क्यों आ रही है तेजी

पश्चिम एशिया में लंबे समय से चल रहे भू-राजनीतिक संघर्ष, आरबीआई सहित कई केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, भौतिक मांग की वजह से सोने की कीमतों में तेजी आई है।

क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सोने की बढ़ती कीमतों के बीच मांग में कमी से निपटने के लिए खुदरा विक्रेता इस वित्तीय वर्ष में मार्केटिंग और प्रमोशनल अभियान बढ़ा सकते हैं। ऐसे में परिचालन से होने वाला मुनाफा साल-दर-साल 20-40 आधार अंक (100 आधार अंक 1 प्रतिशत अंक के बराबर है) से मामूली रूप से कम होकर 7.7-7.9 प्रतिशत हो सकती है।

क्या होता है मैटरनिटी इन्शुरन्स, कैसे करें सही प्लान का चुनाव? यहां जानें जवाब

आज के समय में इंश्योरैंस बहुत जरूरी हो गया है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो वह आपात स्थिति में काफी मददगार साबित होता है। आपको बता दें कि हेल्थ इंश्योरेंस में मेटरनिटी इंश्योरेंस (मैटरनिटी इन्शुरन्स) भी शामिल होता है। आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि मेटरनिटी इंश्योरेंस के फायदे क्या हैं और सही इंश्योरेंस प्लान कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं।

नई दिल्ली। आज के समय में इंश्योरेंस (Insurance) काफी जरूरी हो गया है। मार्केट में कई तरह के इंश्योरेंस मौजूद हैं। देश में इंश्योरेंस लेने वालों की संख्या में लगातार बढ़ रही है। दरअसल, इंश्योरेंस हमें कई तरह से हेल्प करता है।

अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो मेडिकल एक्सपेंस को कम करने के साथ आपात स्थिति में यह काफी मददगार साबित होता है।

इंश्योरेंस की तरह ही हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) भी कई तरह के होते हैं। आपको बता दें कि इसमें मैटरनिटी इंश्योरेंस (Maternity Insurance) भी शामिल है। आज हम आपको बताएंगे कि मैटरनिटी इंश्योरेंस क्या होता है और इसके क्या फायदे हैं?

मैटरनिटी इंश्योरेंस क्या है? (What is Maternity Insurance)

मैटरनिटी इंश्योरेंस भी एक तरह का हेल्थ इंश्योरेंस होता है। इस इंश्योरेंस में प्रेगनेंसी से जुड़े सभी खर्चे कवर होते हैं। कई इंश्योरेंस कंपनियां इस इंश्योरेंस में डिलीवरी से पहले और बाद के खर्चों को कवर करती है। वहीं, कुछ कंपनियां अपनी महिला कर्मचारी को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत ही मैटरनिटी का लाभ देती है।

वहीं कई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में पॉलिसी धारक मैटरनिटी इंश्योरेंस को एक ऐड-ऑन करवा सकता है ताकि इंश्योरेंस में मैटरनिटी के सारे खर्च शामिल हो पाए।

क्या है मैटरनिटी इंश्योरेंस के फायदे (Benefit of Maternity Insurance)

- इसमें आप इंश्योरेंस के साथ बाकी खर्चों को भी ऐड-ऑन करवा सकते हैं।
- कई मैटरनिटी इंश्योरेंस पॉलिसी में वैक्सीनेशन, इंफर्टिलिटी ट्रीट्मेंट आदि के खर्च भी शामिल होते हैं।
- कई कंपनी मैटरनिटी इंश्योरेंस में सरोगेसी और आईवीएफ (IVF) जैसे खर्चों को भी कवर करती है।

सही प्लान कैसे सेलेक्ट करें

- अगर आप मैटरनिटी इंश्योरेंस लेने का सोच रहे हैं तो आपको पहले यह समझ लेना चाहिए कि उसमें क्या-क्या कवर हो रहा है। कंपनी द्वारा मिल रहे कवरेज को समझना आवश्यक है।
- आपको वह प्लान चुनना चाहिए जिसमें ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड जैसे टेस्ट शामिल हो।
- प्री- प्रेगनेंसी वैक्सीन के साथ बच्चों के लिए वैक्सीन कवर करनी वाली इंश्योरेंस पॉलिसी को सेलेक्ट करना चाहिए।
- हमेशा ऐसी मैटरनिटी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए जिसमें पहले दिन से नवजात को कवर किया जाए।

KAL एयरवेज से 450 करोड़ रुपये रिफंड मांगेगी स्पाइसजेट, क्या है इसके पीछे की वजह

परिवहन विशेष न्यूज

स्पाइसजेट दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद एयरलाइन के पूर्व प्रवर्तक कलानिधि मारन और उनकी कंपनी केएएल एयरवेज को भुगतान किए गए कुल 730 करोड़ रुपये में से 450 करोड़ रुपये का रिफंड मांगेगी। बता दें कि इसमें समें मूलधन के 580 करोड़ रुपये और ब्याज के अतिरिक्त 150 करोड़ रुपये शामिल हैं। आइये इसके बारे में जानते हैं।

नई दिल्ली। स्पाइसजेट ने बुधवार को कहा कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद एयरलाइन के पूर्व प्रवर्तक कलानिधि मारन और उनकी कंपनी केएएल एयरवेज को भुगतान किए गए कुल 730 करोड़ रुपये में से 450 करोड़ रुपये का रिफंड मांगेगी।

अदालत की एक खंडपीठ ने 17 मई को एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को रद्द कर दिया, जिसने एक मध्यस्थ पुरस्कार को बरकरार रखा था, जिसमें स्पाइसजेट और उसके प्रमोटर अजय सिंह को मारन को 579 करोड़ रुपये और ब्याज वापस करने के लिए कहा गया था।

स्पाइसजेट ने दायर की अपील

पीठ ने 31 जुलाई, 2023 को पारित एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली सिंह और स्पाइसजेट द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और मध्यस्थ पुरस्कार को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को संबंधित अदालत में वापस भेज दिया।

इस बैंकग्राउंड में एयरलाइन ने बुधवार को एक नियामक फाइलिंग में कहा कि वह मारन और केएएल एयरवेज को भुगतान किए गए 730 करोड़ रुपये में से 450 करोड़ रुपये की वापसी की मांग करेगी।

एयरलाइन ने कहा कि स्पाइसजेट ने मारन और केएएल एयरवेज को कुल 730 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, जिसमें मूलधन के 580 करोड़ रुपये और ब्याज के अतिरिक्त 150 करोड़ रुपये शामिल हैं। विवादित आदेश को रद्द करने के साथ, स्पाइसजेट को 450 करोड़ रुपये का रिफंड मिलना तय है।

बीएसई पर दोपहर के कारोबार में स्पाइसजेट के शेयर 2.62 प्रतिशत बढ़कर 62.60 रुपये पर पहुंच गए।

पेटीएम पर दिखा RBI के एक्शन का असर, बढ़ गया कंपनी का घाटा और लुढ़क गए शेयर

परिवहन विशेष न्यूज

फिनटेक कंपनी पेटीएम (Paytm) ने मार्च तिमाही के नतीजे जारी कर दिये हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ एक्शन लिया है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। आरबीआई के इस फैसले का असर कंपनी के वित्तीय स्थिति पर भी देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं कि मार्च तिमाही में पेटीएम की आर्थिक स्थिति कैसी रही?

नई दिल्ली। आज सुबह फिनटेक फर्म वन97 कम्युनिकेशंस (One 97 Communications Ltd) ने मार्च तिमाही के नतीजों का एलान किया है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि मार्च तिमाही में उनका नेट लॉस 550 करोड़ रुपये हो गया है। एक साल पहले इसी अवधि में कंपनी को 167.5 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

अगर पूरे कारोबारी साल की बात करें तो 31 मार्च 2024 को समाप्त साल में कंपनी का घाटा कम होकर 1,422.4 करोड़ रुपये रह गया। Paytm ने FY23 में 1,776.5 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया था।

इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में पेटीएम के ऑपरेशनल रेवेन्यू 2.8 प्रतिशत घटकर 2,267.1 करोड़ रुपये हो गया, जो वित्तीय वर्ष 2023 की इसी तिमाही में 2,464.6 करोड़ रुपये था।

हालांकि, पेटीएम का वार्षिक राजस्व वित्त वर्ष 2023 में 7,990.3 करोड़ रुपये से लगभग 25 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 9,978 करोड़ रुपये हो गया।

क्यों खराब हो रही है कंपनी की आर्थिक स्थिति

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 15 मार्च से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (Paytm Payments Bank Ltd) को किसी भी ग्राहक खाते, वॉलेट और फास्टैग में जमा, क्रेडिट लेनदेन या टॉप-अप स्वीकार करने से रोक दिया है। आरबीआई के इस फैसले का असर कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर भी पड़ा है।

पेटीएम ने आरबीआई द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बाद अनुमान लगाया था कि कंपनी को आरबीआई के फैसले की वजह से 300-500 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।

पेटीएम को Q2FY25 से मजबूत राजस्व वृद्धि और बेहतर लाभप्रदता की उम्मीद है। कंपनी बैंक भागीदारी के माध्यम से वित्तीय उत्पाद वितरण का विस्तार करने और ग्राहक प्रतिधारण और सेवा को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

पेटीएम के शेयर की परफॉर्मेंस

अगर पेटीएम के शेयर (Paytm Share) की बात करें तो कंपनी के शेयर आज भी 5 फीसदी गिर गए हैं। खबर लिखते वक्त पेटीएम के शेयर की कीमत 346.40 रुपये प्रति शेयर थी। पिछले 1 महीने में कंपनी के शेयर ने 8.34 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है।

वहीं 1 साल में कंपनी के शेयर ने निवेशकों को 51.01 प्रतिशत का नेगेटिव रिटर्न दिया है। बीएसई वेबसाइट के अनुसार पेटीएम की पेरेंट कंपनी One 97 Communications Ltd का एम-कैप 10,785.46 करोड़ रुपये है।

RBI ने केंद्र सरकार को दिया डिविडेंड का तोहफा, जल्द ट्रांसफर होगी 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपये के लाभांश भुगतान को मंजूरी दे दी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के मुकाबले इस बार आरबीआई दोगुना से ज्यादा राशि का भुगतान करेगा। यह निर्णय गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 608वीं बैठक में लिया गया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार आरबीआई ने एक बयान में कहा कि बोर्ड ने लेखा वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 2,10,874 करोड़ रुपये के हस्तांतरण को मंजूरी दी। कारोबारी साल 2022-23 में आरबीआई ने सरकार को 87,416 करोड़ रुपये का लाभांश दिया था।

क्या है सरकार का लक्ष्य केंद्र सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे और राजस्व के बीच अंतर को 17.34 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 5.1 प्रतिशत) तक सीमित रखना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में सरकार ने आरबीआई और पब्लिक सेक्टर के वित्तीय संस्थानों से 1.02 लाख करोड़ रुपये की लाभांश आय का अनुमान लगाया था।

इन विषयों पर हुई चर्चा आरबीआई बोर्ड ने विकास परिदृश्य के जोखिमों सहित वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य की भी समीक्षा की। इसके अलावा बोर्ड ने 2023-24 के दौरान रिजर्व बैंक के कामकाज पर चर्चा की और पिछले वित्त वर्ष के लिए इसकी वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण को मंजूरी दी।

बैन हटने के बाद अनियन एक्सपोर्ट में आई तेजी, 45000 टन से ज्यादा प्याज का हुआ निर्यात

परिवहन विशेष न्यूज

सरकार ने 4 मई को अनियन एक्सपोर्ट पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। पिछले साल प्याज की चढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। प्रतिबंध हटने के बाद अभी तक 45000 टन से ज्यादा प्याज का निर्यात हो गया है। राज्य के स्वामित्व वाली एजेंसियों ने बफर स्टॉक बनाने के लिए प्याज की खरीद शुरू कर दी है।

नई दिल्ली। पिछले साल सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि इस प्रतिबंध को अब सरकार ने हटा दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अधिकारी का हवाला देते हुए बताया कि इस महीने की शुरुआत में आउटबाउंड शिपमेंट पर प्रतिबंध हटने के बाद से भारत ने 45,000 टन से अधिक प्याज का निर्यात किया है।

आम चुनावों से पहले घरेलू आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए प्रतिबंध लगाए जाने के बाद इन निर्यातों ने किसानों को राहत प्रदान की।

दुनिया के सबसे बड़े सब्जी निर्यातक ने पिछले दिसंबर में बल्ब के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया और फिर सुस्त उत्पादन के कारण कीमतों में वृद्धि के बाद मार्च में इसे बढ़ा दिया।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की सचिव निधि खरे ने पीटीआई-भाषा को बताया कि

"प्याज पर प्रतिबंध हटने के बाद से 45,000 टन से अधिक प्याज का निर्यात किया गया है। यह निर्यात ज्यादातर मध्य पूर्व और बांग्लादेश में हुआ है। इस साल अच्छे मानसून के पूर्वानुमान से जून से प्याज सहित खरीफ (ग्रीष्मकालीन) फसलों की बेहतर बुआई सुनिश्चित होगी।"

इसके आगे उन्होंने कहा कि राज्य के स्वामित्व वाली एजेंसियों ने चालू वर्ष के लिए लक्षित 5,00,000 टन का बफर स्टॉक बनाने के लिए हालिया रबी (सर्दियों) की फसल से प्याज की खरीद शुरू कर दी है।

चुनाव अवधि के दौरान प्याज की कीमतें सस्ती रखने के लिए सरकार ने 4 मई को प्रतिबंध हटा दिया था। वहीं सरकार ने न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) 550 अमेरिकी डॉलर प्रति टन कर दिया।

कृषि मंत्रालय के पहले अनुमान के अनुसार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में कम उत्पादन के कारण 2023-24 फसल वर्ष में देश का प्याज उत्पादन एक साल पहले से 16 प्रतिशत गिरकर 25.47 मिलियन टन होने की उम्मीद है।

गर्मी-बारिश ने क्यों बढ़ा दी किसानों और सरकार की टेंशन?

परिवहन विशेष न्यूज

उत्तर भारत में भीषण गर्मी के प्रकोप ने सरकार और किसान दोनों की चिंता को बढ़ा रखी है। कई इलाकों में रेड रॉट (गन्ने में लगने वाले लाल सड़न रोग) और टॉप बोरर (सफेद तितली वाला कीड़ा) का प्रकोप देखा जा रहा है। ये दोनों कीट फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

इन देश के उत्तर भारत के राज्यों के अलावा राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कई शहरों में पारा 45 डिग्री को पार कर चुका है। मौसम विभाग ने दिनों के लिए कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। जबकि दक्षिण भारत के तमाम इलाकों में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इसी मौसम ने एक तरफ किसानों की नींद उड़ा रखी है, दूसरी तरफ सरकार की भी टेंशन बढ़ा दी है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही गन्ना और दाल को लेकर एडवाइजरी जारी कर सकती है।

दरअसल, उत्तर भारत में भीषण गर्मी के प्रकोप ने सरकार और किसान दोनों की चिंता को बढ़ा रखी है। कई इलाकों में रेड रॉट (गन्ने में लगने वाले लाल सड़न रोग) और टॉप बोरर (सफेद तितली वाला कीड़ा) का प्रकोप देखा जा रहा है। ये दोनों कीट फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर समय रहते इन कीटों की रोकथाम नहीं की गई, तो इससे गन्ने की फसल के उत्पादन पर असर पड़ सकता है। गन्ना किसानों की मुख्य फसलों में से एक है। इस पर बड़ी संख्या में किसानों की आय निर्भर करती है।

जानकारी के मुताबिक, फिलहाल जिलों से इसकी रिपोर्ट राजधानी दिल्ली में भेज दी गई है। जिला स्तर पर कई जगह एडवाइजरी जारी की गई है। सरकार भी पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में सरकार जल्द ही एडवाइजरी जारी कर सकती है। राज्यों को प्रभावित लोकेशन के लिए जरूरी निर्देश दिए जा सकते हैं और जरूरी दवा और अवेयरनेस कार्यक्रम बढ़ाने के लिए कहा जा सकता है।

दूसरी तरफ, दक्षिण भारत में बारिश के चलते अलर्ट जारी किया गया है। दाल की बुवाई को सुचारू रखने के लिए राज्य स्तर पर कार्रवाई की जा रही है और किसानों को वाटर लॉगिंग की स्थिति से बचाव करने के लिए कहा गया है। साथ ही मौसम के अनुसार बुवाई के लिए जिला स्तर पर कार्यक्रम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसे लेकर भी सरकार की ओर से जल्द ही एडवाइजरी जारी की जा सकती है।

आम आदमी की दाल में लगा महंगाई का तड़का, क्यों हो रही महंगी?

बाजार के जानकारों का कहना है कि अरहर, चना और उड़द की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। बावजूद इसके दालों के दाम बढ़े हुए हैं। अक्तूबर महीने में जब बाजार में दाल की नई फसल की आवक शुरू होगी, तभी कीमतों में कमी देखी जाएगी। पिछले साल भी अरहर दाल का उत्पादन कम था। जिसके चलते स्टॉक भी कम हुआ था। इससे कीमतों पर असर देखा जा रहा है।

नई दिल्ली। आम आदमी की थाली की अब दाल भी महंगी होने जा रही है। दालों की कीमतों में कम से कम अगले पांच माह तक कमी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे सबसे अहम कारण दालों की सप्लाई और डिमांड में अंतर बताया जा रहा है। ज्यादा डिमांड और कम सप्लाई के चलते दालों की कीमत बढ़ रही है। हालांकि, सरकार दालों की कीमतों को नीचे लाने के लिए प्रयास कर रही है।

दरअसल, दालों की बढ़ते दाम सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है। क्योंकि पिछले 11 महीने से दालों की महंगाई दर दोहरे अंक में है। जानकारों का भी कहना है कि, वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही के अंत तक दालों के दाम कम होने की संभावना है। अप्रैल में दालों की महंगाई दर 16.8 फीसदी दर्ज की गई। इसमें अरहर दाल की महंगाई दर 31.4 फीसदी, चना 14.6 फीसदी और उड़द 14.3 फीसदी दर दर्ज की गई थी। इसके चलते अप्रैल में खाद्य मुद्रास्फीति पिछले महीने के 8.5 फीसदी से बढ़कर 8.7 फीसदी पर पहुंच गई थी।

बाजार के जानकारों का कहना है कि अरहर, चना और उड़द की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। बावजूद इसके दालों के दाम बढ़े हुए हैं।

अक्तूबर महीने में जब बाजार में दाल की नई फसल की आवक शुरू होगी, तभी कीमतों में कमी देखी जाएगी। पिछले साल भी अरहर दाल का उत्पादन कम था। जिसके चलते स्टॉक भी कम हुआ था। इससे कीमतों पर असर देखा जा रहा है।

दाल का व्यापार करने वाले व्यापारियों का कहना है कि सरकार दालों के दाम कंट्रोल करने के लिए कई स्तरों पर कोशिशें कर रही है। लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिल रही है। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन यहां पर इनकी खपत उत्पादन से भी कहीं ज्यादा है। ऐसे में भारत को दालों की डिमांड पूरी करने के लिए आयात का सहारा लेना पड़ता है। व्यापारियों ने इस बात की भी चिंता जताई है कि यदि मानसून की स्थिति अनुकूल नहीं रही, तो दाल की महंगाई दर और भी लंबी अवधि तक ऊंची रह सकती है। क्योंकि, दालों की बुवाई मानसून के बाद जून-जुलाई में होगी और कटाई अक्तूबर-नवंबर में होगी।

तप और वैराग्य शक्ति

स्वामी विवेकानंद

गतांक से आगे'....

जिससे स्वामी जी का चरित्र भ्रष्ट हो जाए और वह उनके खिलाफ प्रचार करें। जब उनको इसमें कामयाबी हासिल न हो सकी तो फिर स्वामी जी में डर बिठाकर प्रचार कार्य को रोकने की कोशश करने लगे। वे विचारे ये नहीं जानते थे कि अभय तो भारतीय अध्यात्म साधाना की पहली शर्त है। स्वामी जी अपनी प्रशंसा को सुनकर न तो घमंड में डूबे थे और न ही अपनी निंदा को सुनकर विचलित हुए थे। वे पूरे जी जान से अपने प्रचार कार्य में लगे रहे। स्वामी जी के मित्र व स्नेही कदम-कदम पर उन्हें सावधान करते रहते थे। उनका यह भी कहना था कि लोकाचार की निंदा न करके सब प्रिय लगने वाली बातें ही व्याख्यानों में कही जाएं। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि भारतीय संन्यासी किसी और धातु का ही बना है। उन्होंने किसी की भी एक बात नहीं सुनी और न्याय पथ को न छोड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। स्वामी जी की सफलता की खबरें भारत में भी पहुंच रही थीं। हिंदू लोग संन्यासी के कार्यों का विवरण कौतूहल व आग्रह के साथ सुनने लगे। रामानंद तथा खेतरी के राजाओं ने, जो स्वामी जी के शिष्य भी रह चके थे, अपने गुरुदेव की सफलता का सारी प्रजा में बखान किया था, स्वामी जी की सफलता पर अनेकों बधाई पत्र मिले। मद्रास के अंदर जहां उत्साही शिष्यों ने विशेष अनुरोध कर स्वामी जी को धर्म सभा में सम्मिलित किया था, वहां रामास्वामी मुदलियार और दीवान बहादुर पर सुब्रह्मण्यम अययर महोदय के नेतृत्व में एक विराट सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में सर्वसम्मति से स्वामी जी के प्रचार कार्य का अभिनंदन किया और उन्हें बधाई पत्र लिखा।

कलकत्ता जो स्वामी जी की जन्म भूमि थी, वहां के लोगों में तो उत्साह व आनंद की लहर दौड़ गई थी, यहां भी एक विशाल सभा का आयोजन हुआ और सभी बाइज्जत लोग उसमें शामिल भी थे। स्वामी जी के प्रचार कार्य की सराहना की गई और इस महान कार्य के लिए उनका धन्यवाद किया गया। शिकागो धर्मसभा के सभापति श्री बैरोज महोदय का भी इस सभा ने शुक्रिया किया। पूरे देश में नवजागरण की एक लहर सी दौड़ गई। आत्महीनता के भाव आत्मगौरव में बदल गए। एक व्यक्ति ने अपनी शक्ति से पूरे देश के मनुष्यों को आत्म गौरव की चेतना से भर दिया। यह शक्ति तप और वैराग्य शक्ति थी। यह शक्ति ब्रह्म की शक्ति थी, यह आत्मा परमात्मा की शक्ति थी। शिकागो की धर्मसभा समाप्त हो जाने के बाद स्वामी जी लगभग एक वर्ष तक शहर-शहर घूमकर प्रचार करते रहे। उनके सभी भाषणों की प्रतिलिपियां नहीं रखी जा सकीं। वे लिखित भाषण नहीं देते थे। यहां तक कि शिकागो धर्म सभा में भी उन्होंने अलिखित भाषण ही दिया। उस वक्त की पत्र-पत्रिकाओं में बहुत सी सामग्री न्यूज पेपरों आदि में प्रकाशित हुई। सन-1814 में डेट्राइट यूनिटेरिअस चर्च में एक प्रचार स्वामी जी ने किया था। मार्च, अप्रैल, मई, जून इन महीनों में उन्होंने शिकागो, न्यूयार्क, बोस्टन शहरों में प्रचार किया। जून में वह गीवएकर के एक सम्मेलन में भाषण देने के लिए गए।

भारतीय लोकतंत्र में पसमांदा (भारतीय मुसलमानों) की भूमिका शारिक अदीब अंसारी : प्रो. देवेंद्र कुमार धूसिया

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। पसमांदा, एक फारसी शब्द जिसका अर्थ है 'जो पीछे रह गए हैं', भारत में आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिए पर रहने वाले मुस्लिम समुदायों को संदर्भित करता है। इस समूह में मुख्य रूप से पिछड़ी जाति (अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी पसमांदा) और दलित (दलित पसमांदा) शामिल हैं। भारत में मुस्लिम आबादी का बहुमत होने के बावजूद, पसमांदा ने ऐतिहासिक रूप से बहिष्कार और भेदभाव का सामना किया है, न केवल व्यापक समाज के भीतर बल्कि मुस्लिम समुदाय के भीतर भी।1944 में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए जाति सर्वेक्षण के अनुसार 85 से 88% भारतीय पसमांदा आबादी अजलाफ़ (ओबीसी) और अरजाल (एससी/एसटी) थी क्योंकि कोई पसमांदा शब्द नहीं था, उस समय पसमांदा शब्द भारतीय पसमांदा के समूह द्वारा गढ़ा गया था, जो पसमांदा के साथ भेदभाव के कारण कांग्रेस से अलग हो गए थे, इसे अखिल भारतीय तबकाती मुस्लिम पसमांदा फेडरेशन ऑफ इंडिया कहा जाता था, जिसने 14 नवंबर 1979 को बुधवार को नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में अपना पहला समारोह आयोजित किया था। ओबीसी और दलित पसमांदा की आबादी ब्रिटिश भारत में कुल मुस्लिम आबादी का लगभग 85% से 88% है। इस समाज की अधिकांश आबादी गरीबी से बुरी तरह प्रभावित है क्योंकि इस समाज की अधिकांश आबादी शिल्प, कौशल, भूमिहीन श्रमिक, कुपोषण से प्रभावित है। रोजगार के लिहाज से जमींदारों की भूमि और खेतों में उनके साथ गुलामों की तरह व्यवहार किया जाता था। हालात इतने खराब थे कि अशरफिया चाहते थे कि वह जैसे है वैसे ही रहे।

राजनीतिक जागृति और गतिशीलता पसमांदा की राजनीतिक जागृति का पता विभिन्न सामाजिक आंदोलनों और उनके उत्थान के लिए समर्पित संगठनों के गठन से लगाया जा सकता है। पसमांदा मुद्दों को सामने लाने में प्रमुख हस्तियों और आंदोलनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है:

मौलाना असीम बिहारी और अब्दुल कयूम अंसारी: दो किंवदंती पसमांदा आंदोलन के लिए देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं जहां अशराफिया पिछड़े मुसलमानों को अपनी अलग पहचान के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। 1930 के दशक में पिछड़े मुसलमानों के लिए मोमीन आंदोलन, एक राजनीतिक दल का गठन किया जिसने बिहार में 5-6 सीटें जीतीं। मोमीन सम्मेलन 1926-1936 तक एक कल्याणकारी और सुधारवादी संगठन था, लेकिन 1937 के बाद दो-राष्ट्र सिद्धांत और पाकिस्तान की मांग का विरोध करते हुए अधिक राजनीतिक हो गया। असीम बिहारी ने लंबी बीमारी के बाद 1953 में इलाहाबाद में अपनी मृत्यु तक मोमीन सम्मेलन की सेवा जारी रखी। अब्दुल माजिद अदीब अंसारी और हाजी कामिल कुरैशी: अखिल भारतीय स्तर पर अम्ब्रेला एसोसिएशन बनाकर पसमांदा आंदोलन को ऊंचाइयों पर ले गए जबकि पसमांदा मुस्लिम फेडरेशन धर्मनिरपेक्ष भारत की सभी पिछड़ी और दलित जातियों का गठन करने वाला एक निकाय था, यह भारतीय मुसलमानों की सभी अजलाफ और अरजल जातियों की एक इकाई थी। यह पहला एकजुट निकाय था। पहली विशाल सार्वजनिक सभा 14 नवंबर, 1979 को ऐतिहासिक तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित की गई थी, जहाँ भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा समारोह के मुख्य अतिथि थे। इस समारोह के द्वारा भारत में पहली बार पसमांदानाम का प्रयोग किया गया। डॉ. एजाज अली: वरिष्ठ हड्डी रोग सर्जन जो 30 से अधिक वर्षों से पटना में प्रैक्टिस कर रहे हैं, समाज के विशेष रूप से हाशिये पर रहने वालों को लगभग मुफ्त सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा वे वरिष्ठ पसमांदा आंदोलन के नेता और भारत के पिछड़े मुस्लिम मोर्चा के संस्थापक हैं, जिनके झंडे के नीचे उन्होंने भारत में पसमांदा आंदोलन के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। उन्हें बिहार से राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है जहाँ उन्होंने हमेशा पसमांदासे संबंधित मुद्दों को उठाया। अली अनवर अन्सारी: एक प्रमुख पसमांदानेता और पसमांदा मुस्लिम महाज (पसमांदा मुस्लिम फ्रंट) के संस्थापक अंसारी ने राजनीति में पसमांदाके अधिकारों और प्रतिनिधित्व की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

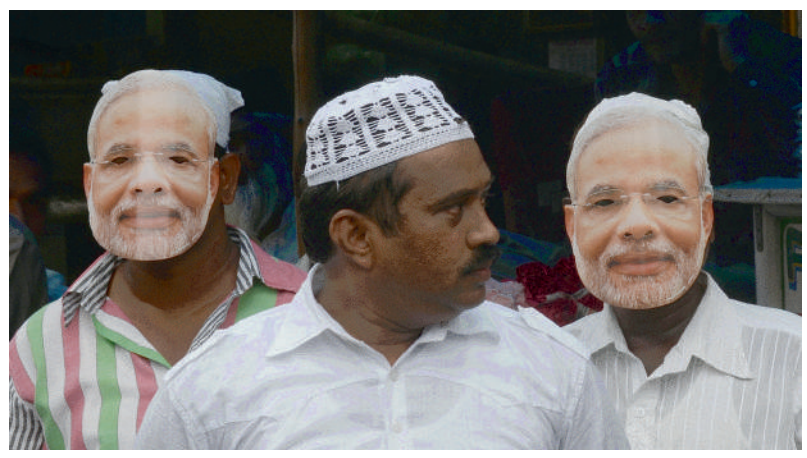

पसमांदा क्रांति: पसमांदा क्रांति/आंदोलन पसमांदा के सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण शक्ति रहा है।

इन प्रयासों से पसमांदा के बीच राजनीतिक चेतना का विकास हुआ है, जिससे अब पसमांदा समाज समावेश और प्रतिनिधित्व की अपनी मांगों के बारे में अधिक मुखर हैं। पसमांदा का राजनीतिक प्रतिनिधित्व आनुपातिक रूप से उनकी आबादी को प्रदर्शित नहीं करता है क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकांश पद दशकों से अशरफिया के स्वामित्व में हैं। पसमांदा का प्रतिनिधित्व अक्सर उनके जनसांख्यिकीय प्रतिशत से कम रहा है। यह कम प्रतिनिधित्व नीति को प्रभावित करने और अपने हितों की रक्षा करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करता है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों राजनीतिक दलों ने पसमांदा मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण अलग-अलग रखा है। वर्तमान भाजपा सरकार ने पसमांदा का मुद्दा उठाया क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पसमांदा और समाज में उनकी स्थिति के सुधार की वकालत करते हैं, जबकि कुछ पार्टियों ने ऐतिहासिक रूप से इस मुद्दे को उठाया है।जबकि कुछ दलों ने ऐतिहासिक रूप से पर्याप्त पसमांदा समर्थनहासिल किया है। इस समाज का प्रतीकात्मक (tokenism) उपयोग और चुनावी लाभ के लिए धार्मिक भावनाओं के शोषण को लेकर चिंताएं व्याप्त हैं। सामाजिक-आर्थिक संकेतक

पसमांदा की सामाजिक-आर्थिक स्थिति की जड़ें जाति व्यवस्था में हैं, जो आधिकारिक तौर पर इस्लामी शिक्षा का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसने भारतीय मुस्लिम समाज को गहराई से प्रभावित किया है। ऐतिहासिक रूप से असराफ़ (जो विदेशी या कुलीन वंश का दावा करते हैं) पसमांदा पर सामाजिक और राजनीतिक प्रभुत्व बनाए रखा है, जो अक्सर पसमांदा को दरकिनार करते हैं। इस हाशिए के कारण शिक्षा, रोजगार और राजनीति में पसमांदा का प्रतिनिधित्व कम हो गया है। पसमांदा ने देश के सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि, उन्हें सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सच्चर समिति की रिपोर्ट (2006) सहित रिपोर्ट अन्य समुदायों की तुलना में पसमांदा के बीच शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच में असमानताओं को उजागर करती है।

शिक्षा: पसमांदा के बीच जबकि साक्षरता दर में सुधार हुआ है, वे अभी भी राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं। शैक्षणिक अवसरों को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उनके स्कूल छोड़ने की दर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच जैसे मुद्दे बने हुए हैं क्योंकि अधिकांश शैक्षणिक संस्थान अशरफिया द्वारा शासित हैं और वे नहीं चाहते थे कि पसमांदा पेशेवर पाठ्यक्रमों का अध्ययन करें ताकि उन्हें सत्ता और राजनीति से दूर रखा जा सके।

रोजगार: औपचारिक रोजगार क्षेत्रों में पसमांदा का प्रतिनिधित्व कम है और अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्रों में कारीगर, टर्नर, वेल्डर, नलसाज, बिजली मिस्त्री, बढ़ई एवं मजदूर और कई और कुशल और अकुशल नौकरियों में अधिक प्रतिनिधित्व दिखता है। सरकारी नौकरियों और निजी क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की कमी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है।

जीवन स्थिति: कई पसमांदा अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और सेवाओं के साथ सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में रहते हैं। शहरी घेटो और ग्रामीण गरीबी समुदाय के हाशिए पर जाने को विवश हैं।

प्रगति और सकरात्मक विकास: चुनौतियों के बावजूद, विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। पसमांदा ने कला, खेल, व्यवसाय और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता में सुधार के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा की गई पहल धीरे-धीरे फल दे रही है। सामुदायिक नेता और कार्यकर्ता तेजी से बेहतर नीतियों और प्रतिनिधित्व की वकालत कर रहे हैं। सोशल मीडिया के उदय ने युवा पसमांदा को अपनी चिंताओं और आकांक्षाओं को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए सशक्त किया है।

भारतीय लोकतंत्र में पसमांदा की स्थिति भारतीय लोकतंत्र, जो दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अपने बहुलवाद और विविधता की विशेषता है, जिसमें एक महत्वपूर्ण मुस्लिम आबादी शामिल है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 14.2% आबादी वाले भारतीय मुस्लिम पसमांदा देश के सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समानता और धर्मनिरपेक्षता की संवैधानिक गारंटी के बावजूद, समकालीन लोकतंत्र में भारतीय पसमांदा की स्थिति बहुआयामी है, जिसमें प्रगति, चुनौतियां और समावेश और प्रतिनिधित्व के बारे में चल रही बहसें शामिल हैं। विधायी प्रतिनिधित्व को अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, पसमांदा नेताओं के विधायी निकायों के लिए चुने जाने के उदाहरण हैं, लेकिन पसमांदा की विशिष्ट चिंताओं और मुद्दों को उठाने के लिए उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है।

उत्थान: भारतीय लोकतंत्र के लिए अपने बहुलवादी लोकाचार को सही मायने में मूर्त रूप देने के लिए, पसमांदा के सामने आने वाली असमानताओं और चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है:

समावेशी नीतियाँ: ऐसी नीतियाँ तैयार करना और लागू करना जो सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं और पसमांदा के अधिकारों की रक्षा करती हैं।

शैक्षिक सुधार: युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच सुनिश्चित करना।

कानूनी सुरक्षा: पसमांदा के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करना अति आवश्यक है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व: निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में राजनीतिक प्रतिनिधित्व और पसमांदा की भागीदारी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है ताकि संविधान के उद्देश्य में निहित राजनीतिक न्याय को प्राप्त किया जा सकता है।

सामुदायिक पहल: सामाजिक-आर्थिक विकास और एकीकरण को बढ़ावा देने वाली समुदाय-संचालित पहलों को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष भारतीय लोकतंत्र में भारतीय पसमांदा की स्थिति एक जटिल और विकसित होने वाला मुद्दा है। भारतीय राजनीति में पसमांदा की भूमिका उनकी अनूठी चुनौतियों और योगदान की बढ़ती मान्यता के साथ विकसित हो रही है। हालांकि महत्वपूर्ण उपलब्धियां और योगदान रहे हैं, लेकिन ऐसी चुनौतियां बनी हुई हैं जिन्हें सरकार, नागरिक और स्वयं समुदाय द्वारा ठोस प्रयासों के माध्यम से हल करने की आवश्यकता है। भारतीय पसमांदा के लिए समानता, न्याय और समावेश सुनिश्चित करना न केवल एक संवैधानिक जनादेश है, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक आदर्शों की सच्ची प्राप्ति के लिए भी आवश्यक है। भारत में अधिक समावेशी और न्यायसंगत राजनीतिक परिदृश्य के लिए उनकी सक्रिय भागीदारी और प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है।

हरियाणा में राहुल का दांव, बोले- किसानों का कर्ज माफ नहीं, मगर पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ का ऋण माफ

हरियाणा में राहुल गांधी की जनसभाओं को कांग्रेस पार्टी के लिए अहम माना जा रहा है। प्रदेश की दस लोकसभा सीटों में से तीन चार सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार, भाजपा प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इन सीटों में रोहतक, सोनीपत और हिसार शामिल हैं।

हरियाणा में लोकसभा चुनाव का धुआंधार प्रचार करते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 'किसानों' और 'अग्निवीरों' का दांव चल दिया है। बुधवार को चरखी दादरी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, मोदी सरकार चंद पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपये का ऋण माफ कर सकती है, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं करेगी। चार जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आने पर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। राहुल ने कहा, हरियाणा के युवा देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। अग्निवीर योजना में शहीद होने पर युवाओं को न शहीद का दर्जा मिलेगा, न ही पेंशन मिलेगी और न कोई अन्य सुविधा। चार साल बाद वे युवा, फिर से बेरोजगारों की कतार में खड़े हो जाएंगे।

हरियाणा में राहुल गांधी की जनसभाओं को कांग्रेस पार्टी के लिए अहम माना जा रहा है। प्रदेश की दस लोकसभा सीटों में से तीन चार सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार, भाजपा प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इन सीटों में रोहतक, सोनीपत और हिसार शामिल हैं। किसान आंदोलन के चलते प्रदेश में खासतौर से जाट समुदाय, भाजपा के प्रति नाराज बताया जा रहा है। इसके बाद पहलवानों के आंदोलन में यह नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के समय भी कई ऐसी घटनाएं हुई, जिनसे किसान वर्ग, सरकार से दूर होता चला गया। हरियाणा से सेना में भर्ती होने वाले युवाओं की अच्छी खासी तादाद है। 'अग्निपथ' योजना से प्रदेश के युवाओं में नाराजगी बताई गई है। अब राहुल गांधी ने हरियाणा में मतदान से तीन दिन पहले किसानों और अग्निवीरों का मुद्दा उठा दिया है। उन्होंने इन दोनों वर्गों के लिए चुनावी घोषणा कर दी हैं।

राहुल ने कहा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर अग्निवीर योजना, रद्द की जाएगी। किसानों का कर्ज माफ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झूठी छवि का गुब्बारा फट गया है। हरियाणा में कांग्रेस की आंधी चल रही है। मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर, हिंदुस्तान के जवानों को मजदूरों में बदल दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, हरियाणा के युवा देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। अग्निवीर योजना में शहीद होने पर युवाओं को न शहीद का दर्जा मिलेगा, न ही पेंशन मिलेगी। उन्हें न ही कोई अन्य सुविधा मिलेगी। चार साल बाद युवा फिर बेरोजगार हो जाएंगे। अग्निवीर योजना सेना की योजना नहीं थी, यह प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा बनाई गई थी। कांग्रेस की सरकार किसानों की जमीन की रक्षा करने और उसके सही दाम दिलाने के लिए भूमि अधिग्रहण बिल लाई थी।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023